

बाबा तालाब के सौंदर्यीकरण की मांग को मिला जनसमर्थन, 170 से अधिक लोगों ने किए हस्ताक्षर

बरमकेला/मूक पत्रिका

नगर पंचायत बरमकेला के इंदिरा चौक स्थित लगभग 50 वर्ष पुराने बाबा तालाब के सौंदर्यीकरण, संरक्षण एवं पुनर्जीवन की मांग को लेकर वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 के नागरिकों ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। तालाब की बदहाल स्थिति को देखते हुए चलाए गए हस्ताक्षर अभियान में 170 से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर अपनी सहमति जताई। इस अभियान को स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला है। हस्ताक्षर अभियान में नगर पंचायत उपाध्यक्ष राजू नायक, वार्ड क्रमांक 07 की पार्षद उर्मिला सिदार तथा वार्ड क्रमांक 09 की पार्षद गरिमा पटेल ने भी हस्ताक्षर कर तालाब के विकास की मांग का समर्थन किया।

नगर की पुरानी धरोहरों में शामिल है बाबा तालाब-इंदिरा चौक स्थित बाबा तालाब लगभग 50 वर्ष पुराना माना जाता है और लंबे



समय तक यह आसपास के नागरिकों की आवश्यकताओं का प्रमुख केंद्र रहा है। स्थानीय बुजुर्गों के अनुसार एक समय था जब वार्ड के अधिकांश लोग इसी तालाब का उपयोग नहाने-धोने सहित दैनिक कार्यों के लिए करते थे। लेकिन तालाब की लगातार बिगड़ती स्थिति, गंदगी और प्रदूषण के कारण पिछले लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय से इसका उपयोग नहाने-धोने के लिए लगभग बंद हो चुका है। आज यह तालाब अपनी पुरानी



पहचान खोता जा रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय रहते इसके संरक्षण और विकास की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो यह महत्वपूर्ण जलस्रोत पूरी तरह उपेक्षित हो सकता है। **वरिष्ठ नागरिक पीतांबर नायक ने चलाया हस्ताक्षर अभियान**-तालाब के संरक्षण और सौंदर्यीकरण की मांग को लेकर वार्ड के वरिष्ठ नागरिक पीतांबर नायक ने पहल करते हुए हस्ताक्षर अभियान चलाया। उन्होंने वार्डवासियों से

संपर्क कर तालाब की वर्तमान स्थिति और उसके महत्व को लेकर जनजागरण किया। अभियान को व्यापक समर्थन मिला और 170 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर प्रशासन से तालाब के विकास की मांग की।

सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च हुई राशि, लेकिन नहीं बदली स्थिति-स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व में कई बार तालाब के सौंदर्यीकरण के नाम पर शासकीय राशि खर्च की गई, लेकिन उसका

अपेक्षित लाभ दिखाई नहीं दिया। नागरिकों का कहना है कि पिछले पंचवर्षीय कार्यकाल में भी तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए लाखों रुपये खर्च किए गए, लेकिन वास्तविक सुधार के बजाय केवल सीमित निर्माण कार्य कर औपचारिकता पूरी कर दी गई। लोगों के अनुसार तालाब के किनारे पचरी निर्माण जैसे कुछ कार्य तो हुए, लेकिन तालाब की मूल समस्याओं को दूर करने की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं की गई। परिणामस्वरूप कुछ समय बाद तालाब

फिर अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया। **नाली का पानी और गंदगी बनी सबसे बड़ी समस्या**-वार्डवासियों के अनुसार तालाब की सबसे बड़ी समस्या इसमें लगातार पहुंचने वाला गंदा पानी है। मोहल्ले की कई नालियों का पानी बरसात के मौसम सहित पूरे वर्ष तालाब में आकर गिरता है, जिससे पानी प्रदूषित होता रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों द्वारा तालाब में कचरा फेंकने और नियमित निगरानी के अभाव में भी इसकी स्थिति लगातार बिगड़ती

गई। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर जब तक नालियों के पानी को तालाब में जाने से नहीं रोका जाएगा और स्थायी स्वच्छता व्यवस्था नहीं बनाई जाएगी, तब तक समस्या का समाधान संभव नहीं है।

स्थायी समाधान की मांग-ज्ञापन में नागरिकों ने मांग की है कि तालाब का केवल नाममात्र का सौंदर्यीकरण करने के बजाय इसके संरक्षण की स्थायी योजना बनाई जाए। इसके तहत तालाब में गिरने वाले नाली के पानी को रोकने की व्यवस्था, नियमित सफ़ाई, गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, हरित विकास, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक कार्य कराए जाएं। नागरिकों का कहना है कि यदि तालाब की मूल समस्याओं का समाधान कर दिया जाए तो यह न केवल नगर की सुंदरता बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य में एक स्वच्छ और उपयोगी जलस्रोत के रूप में भी विकसित हो सकेगा।

प्रशासन से सकारात्मक पहल की उम्मीद-170 से अधिक लोगों के हस्ताक्षर और जनप्रतिनिधियों के

समर्थन के साथ सौंपे गए इस ज्ञापन ने बाबा तालाब के मुद्दे को फिर से चर्चा में ला दिया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगभग 50 वर्ष पुराना यह तालाब बरमकेला की पहचान और धरोहर का हिस्सा है, इसलिए इसके संरक्षण और विकास के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। अब नागरिकों को उम्मीद है कि नगर पंचायत प्रशासन इस जनभावना को समझते हुए केवल औपचारिक कार्यों तक सीमित न रहकर बाबा तालाब के पुनर्जीवन और समग्र विकास के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाएगा। **क्या कहते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी**:-नगर पंचायत बरमकेला के मुख्य नगर पालिका अधिकारी दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि -आज वार्ड क्रमांक 06 एवं 07 के नागरिकों द्वारा बाबा तालाब के सौंदर्यीकरण संबंधी आवेदन प्राप्त हुआ है। आवेदन में उठाई गई मांगों पर उचित विचार करते हुए प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। शासन स्तर से जो निर्देश आथवा स्वीकृति प्राप्त होगी, उसके आधार पर आगे आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।:-

पान जमुना धान को लेकर फैल रही अप्फाहों से न हों भ्रमित, शासन करेगा शत-प्रतिशत खरीदी: कृषि विकास अधिकारी..

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

खरीफसीजन शुरू होते ही जिले में पान जमुना धान को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और अप्फाहें फैलने लगी हैं। कुछ लोगों द्वारा किसानों के बीच यह बात फैलाई जा रही है कि आगामी खरीफ विपणन वर्ष में सरकार पान जमुना धान की खरीदी नहीं करेगी। इस अप्फाह के कारण कई किसान असमंजस की स्थिति में हैं और धान की बुवाई को लेकर संशय में पड़ गए हैं।इधर, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बरमकेला बसंत कुमार नायक ने इन सभी चर्चाओं का खंडन करते हुए किसानों से अप्फाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शासन की ओर से अब तक ऐसा



कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, जिसमें पान जमुना धान की खरीदी बंद करने की बात कही गई हो। उन्होंने कहा कि किसानों की जितनी पंजीकृत सीमा निर्धारित है, उसके अनुसार शासन द्वारा धान की शत-प्रतिशत खरीदी की जाएगी। इसलिए किसान बिना किसी डर या भ्रम के पान जमुना धान की बुवाई कर सकते हैं।वहीं रेवेला सहकारी समिति सरिया के प्रभारी प्रबंधक विनोद गुप्ता ने भी इस तरह की खबरों को पूरी तरह भ्रामक बताया है। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से ऐसा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। कृषि उपज मंडी

बरमकेला के प्रभारी निरीक्षक नंदकिशोर सोनी ने भी स्पष्ट किया कि समितियों में सामान्य रूप से मोटा और पतला धान खरीदा जाता है तथा किसी विशेष किस्म के धान की खरीदी रोकने संबंधी कोई जानकारी या आदेश उनके पास नहीं है। कृषि क्षेत्र से जुड़े जानकारों का मानना है कि यह अप्फाह किसानों को गुमराह करने की सोची-समझी कोशिश भी हो सकती है। आशंका जताई जा रही है कि कुछ निजी बीज या धान कारोबारियों द्वारा अपने उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए किसानों के बीच इस तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हों। हालांकि अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे केवल शासन और कृषि विभाग से प्राप्त आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करेंगे।

छंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड ने गढ़उमरिया-दरभुड़ा में 814.5 करोड़ रुपये की विस्तार परियोजना के लिए मांगी पर्यावरणीय मंजूरी, डीआरआई, स्टील मेल्टिंग शॉप, रोलिंग मिल, फेरो अलॉय यूनिट और 50 मेगावाट पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव, जनसुनवाई में उठ सकते हैं प्रदूषण, जल दोहन और कृषि भूमि सुरक्षा के सवाल

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ जिले के गढ़उमरिया और दरभुड़ा क्षेत्र में प्रस्तावित विशाल औद्योगिक विस्तार परियोजना को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में चिंता और विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं।



मेसर्स रंगटा संस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत पर्यावरण प्रभाव आकलन एवं पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुसार कंपनी अपने मौजूदा फेरो अलॉय संयंत्र का बड़े पैमाने पर विस्तार करते हुए उसे एकीकृत इस्पात संयंत्र और 50 मेगावाट के कैप्टिव पावर प्लांट में बदलना चाहती है। प्रस्तावित परियोजना की लागत

814.5 करोड़ रुपये बताई गई है। परियोजना के दस्तावेजों के अनुसार वर्तमान में 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में संचालित इकाई का विस्तार कर कुल 11.029 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। कंपनी फेरो मिश्रधातु उत्पादन क्षमता को 30 हजार टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 42,900 टन प्रतिवर्ष करना चाहती है। इसके

अलावा 2.145 लाख टन प्रतिवर्ष डीआरआई संयंत्र, 2.24 लाख टन प्रतिवर्ष स्टील मेल्टिंग शॉप, 2 लाख टन प्रतिवर्ष रोलिंग मिल, 200 टन प्रतिदिन सिंटर प्लांट, 10 टन प्रतिघंटा मेटल रिकवरी प्लांट, 15 टन प्रतिघंटा रीहीटिंग फ़र्नेस तथा 50 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने का प्रस्ताव है।

पर्यावरणीय दस्तावेजों के अनुसार संयंत्र राष्ट्रीय राजमार्ग-49 के समीप गढ़उमरिया और दरभुड़ा गांवों में स्थित होगा। रायगढ़ रेलवे स्टेशन परियोजना स्थल से लगभग पांच किलोमीटर दूर है जबकि झारसुगुड़ा हवाई अड्डा लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।परियोजना के सार्वजनिक दस्तावेज सामने आने के बाद ग्रामीणों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़े लोगों के बीच कई सवाल उठने लगे हैं। क्षेत्र

के लोगों का कहना है कि पहले से ही रायगढ़ जिला उद्योगों और ताप विद्युत संयंत्रों से होने वाले प्रदूषण की गंभीर समस्या झेल रहा है। ऐसे में एक और बड़े इस्पात और ऊर्जा संयंत्र के विस्तार से वायु गुणवत्ता, भूजल स्तर और कृषि क्षेत्र पर अतिरिक्त दबाव पड़ने की आशंका है। ग्रामीणों का कहना है कि परियोजना में डीआरआई, स्टील मेल्टिंग, रोलिंग मिल और फेरो अलॉय जैसी अत्यधिक प्रदूषणकारी गतिविधियां शामिल हैं। इन इकाइयों से धूलकण, फ्लाई ऐश, धात्विक कण और औद्योगिक अपशिष्ट उत्सर्ज होने की संभावना रहती है। लोगों का आरोप है कि उद्योगों के कारण क्षेत्र में पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ी हैं और अब नई परियोजना से स्थिति और गंभीर हो सकती है।

जिले मे अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर संयुक्त कार्रवाई



5 हाईवा एवं 1 जेसीबी मशीन जप्त, खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज बेमेतरा/मूक पत्रिका

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निर्देशानुसार जिले में अवैध खनिज उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम मनोहरपुर, तहसील नांदघाट में निरीक्षण एवं जांच के दौरान खनिज मुरुम एवं मिट्टी के अवैध उत्खनन तथा परिवहन का मामला पाए जाने पर कार्रवाई की गई। संयुक्त दल द्वारा मौके पर 05 हाईवा वाहनों को जप्त

कर सुरक्षा की दृष्टि से थाना मारो चौकी की अभिरक्षा में रखा गया है। वहीं अवैध उत्खनन में प्रयुक्त 01 जेसीबी चैन माउंटेड मशीन को भी जब्त कर नियमानुसार ग्राम कोटवार के सुपुर्द किया गया है। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहनों एवं मशीन के विरुद्ध अवैध उत्खनन एवं परिवहन का प्रकरण दर्ज किया गया है। मामले में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के प्रावधानों के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि खनिज संसाधनों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सतत निगरानी रखी जा रही है तथा ऐसे मामलों में नियमानुसार कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय कर्मचारी संघ ने सौंपा मांगों का ज्ञापन महंगाई भत्ता से लेकर नियमितीकरण तक उठाए कई मुद्दे

रायगढ़/मूक पत्रिका

छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय शांसीक कर्मचारी संघ, जिला रायगढ़ द्वारा कर्मचारियों एवं पेंशनेरों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। संघ ने राज्य सरकार से कर्मचारियों से जुड़ी घोषणाओं और लंबित मामलों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है। संघ द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन में कहा गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पेंशनेरों को भी देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का लाभ प्रदान किया जाए। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी से 2 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, जबकि प्रदेश के लाखों कर्मचारी अब भी इससे वंचित हैं। कर्मचारी संघ ने विधानसभा बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री द्वारा घोषित क्वेश्लेस चिकित्सा सुविधा को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग भी उठाई है। संघ का कहना है कि घोषणा के



बावजूद अब तक इसके नियम और दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ज्ञापन में सेवानिवृत्ति के समय अवकाश नकदीकरण की सीमा बढ़ाने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। संघ ने मध्यप्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिनों के स्थान पर 300 दिनों के अर्जित अवकाश के नकदीकरण की सुविधा देने की मांग की है। इसके अलावा सविदा, दैनिक वेतनभागी एवं अनियमित कर्मचारियों की रिक्त पदों पर नियमित करने तथा उन्हें सेवा सुझा प्रदान करने की मांग रखी गई है। शिक्षक एल.बी. संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से संपूर्ण सेवा लाभ दिए जाने और अनुकंपा नियुक्ति में

लागू 10 प्रतिशत सीलिंग समाप्त कर सभी रिक्त पदों पर नियुक्ति देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। संघ के जिला अध्यक्ष संतोष पांडे ने कहा कि कर्मचारियों और पेंशनेरों से जुड़े इन मुद्दों का समाधान लंबे समय से लंबित है। सरकार द्वारा किए गए वादों और घोषणाओं के अनुरूप शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि कर्मचारियों में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।महिला प्रकोष्ठ को अध्यक्ष माधुरी त्रिपाठी ने कहा कि अपने हक की लड़ई के लिए सभी कर्मचारियों को निस्वार्थ अपनी मांगों को पूर्ति लिए आंदोलन में आना चाहिए।छात्रावास अधीक्षक संघ के जिला अध्यक्ष चंद्र शेखर मिश्रा ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अभी प्रथम बार आंदोलन में शामिल हुए है।

चपका/बस्तर/मूक पत्रिका

(पवन कुमार नाग) - बीते गुरुवार 11 जून 2026 को भारतीय किसान यूनियन टिकैत एवं सर्व समाज के नेतृत्व में चपका क्षेत्र की 22 पंचायतों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों के हजारों ग्रामीणों, किसानों एवं युवाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विशाल रैली एवं जुलूस निकाला। रैली के पश्चात एसडीएम को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से किसानों एवं ग्रामीणों ने क्षेत्र की विभिन्न ज्ज्वलंत समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। किसानों ने समय पर खाद-बीज उपलब्ध कराने, बोधघाट परियोजना का विरोध करते हुए कार्य बंद कराने, पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर नियंत्रण लगाने तथा किसानों को जर्किन एवं डब्बों में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल-डीजल



उपलब्ध कराने की मांग की। इसके साथ ही किसानों की भूमि की सुरक्षा तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग भी की गई। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि किसान आज अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। खेती-किसानी की लागत लगातार बढ़ रही है, जबकि किसानों को आवश्यक संसाधन समय पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। वहीं क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों एवं किसानों की भूमि पर बढ़ते खतरे को लेकर भी गहरी चिंता व्यक्त की गई। भारतीय किसान यूनियन टिकैत एवं सर्व समाज के नेतृत्व में आयोजित

इस आंदोलन के माध्यम से शासन-प्रशासन को किसानों एवं ग्रामीणों की समस्याओं से अवगत कराया गया तथा मांगों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो भविष्य में और बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा।कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के संघागीय अध्यक्ष शिवा स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष रमेश गोयल, ग्रामीण अध्यक्ष जगत्तम कश्यप, जिला उपाध्यक्ष बलिराम पुजारी, जिला उपाध्यक्ष जयंतराम साहू एवं शुभाम सिंह सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सुकमा जिले से जिला अध्यक्ष सुनील सोब्ली, जिला उपाध्यक्ष रमेश कश्यप सहित अन्य जिलों से आए संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने भी कार्यक्रम में भाग लेकर किसानों के संघर्ष को मजबूती प्रदान की।

शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार, बोर्ड परीक्षा परिणामों में वृद्धि और छात्रावासों की बेहतर व्यवस्था पर दिया विशेष जोर

नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों को लेकर कलेक्टर की सरख्त समीक्षा

प्रत्येक शनिवार यूनिट टेस्ट, विषय विशेषज्ञों की कोर टीम गठन एवं समय पर जाति-आय प्रमाण पत्र बनाने के निर्देश

बेमेतरा/मूक पत्रिका

आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के सफ़्त संचालन, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा छात्रावासों की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने शिक्षा विभाग एवं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक ली। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्यगण, छात्रावास अधीक्षक तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान कलेक्टर ने जिले के विभिन्न विद्यालयों की एक-एक कर विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित प्राचार्यों से विद्यालयों की

वर्तमान स्थिति, शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की संख्या, परीक्षा परिणाम एवं आगामी सत्र की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की।

बोर्ड परीक्षा परिणामों में सुधार लाने के लिए ठोस कार्ययोजना बनाने के निर्देश-

कलेक्टर सुश्री ममगाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि जिले के विद्यालयों के परीक्षा परिणामों में इस वर्ष उल्लेखनीय सुधार दिखाई देना चाहिए। इसके लिए सभी शिक्षक एवं प्राचार्य पूर्ण जिम्मेदारी और समर्पण के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को बढ़ाने के

लिए नियमित अध्ययन, सतत मूल्यांकन और प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक है। उन्होंने निर्देश दिए कि विषयवार अध्ययन की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु प्राचार्यों की एक कोर टीम तथा विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की अलग कोर टीम गठित की जाए। ये टीमें शैक्षणिक गतिविधियों की नियमित समीक्षा करते हुए एक व्यवस्थित शैक्षणिक कैलेंडर एवं कार्ययोजना तैयार करेंगी, जिससे पूरे जिले में शिक्षण कार्य समान रूप से संचालित हो सके। कलेक्टर ने विद्यार्थियों की प्रगति का नियमित आकलन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शनिवार

यूनिट टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता का मूल्यांकन होगा तथा कमजोर विषयों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।

10वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र समय पर तैयार करने पर जोर-बैठक में कलेक्टर ने विशेष रूप से हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी के विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्देश दिए कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं के सभी विद्यार्थियों के आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र समय-सीमा में तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न शासकीय योजनाओं में इन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, इसलिए किसी भी विद्यार्थी को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक समन्वय स्थापित कर सभी लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

छात्रावासों में अनुशासन और सुरक्षा

व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश-इसके पश्चात कलेक्टर ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों एवं आश्रमों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी छात्रावास अधीक्षकों को निर्धारित समय पर छात्रावास में उपस्थित रहने तथा छत्र-छात्राओं की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि छात्रावासों में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन व्यवस्था तथा अध्ययन का वातावरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। विद्यार्थियों के छात्रावास आने-जाने के समय का नियमित रिकॉर्ड रखा जाए तथा अनुशासन एवं सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाओं का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश-

बैठक में कलेक्टर ने आगामी शाला प्रवेश उत्सव की तैयारियों की भी

समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता, गणवेश वितरण, पेयजल, स्वच्छता, बिजली एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने निर्देश दिए कि शाला प्रवेश उत्सव को उत्साहपूर्ण एवं प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाए तथा सभी आवश्यक तैयारियां निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण कर ली जाएं।

विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया जाए कि नए प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का विद्यालयों में स्वागत सकारात्मक वातावरण में हो तथा कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। बैठक के अंत में कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने सभी अधिकारियों एवं शिक्षकों से नए शैक्षणिक सत्र को गुणवत्तापूर्ण, अनुशासित एवं परिणामोन्मुख बनाने के लिए टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिए सभी संबंधित विभागों को समन्वित प्रयास करने होंगे।

किसानो की समस्याओं को लेकर जिला किसान कांग्रेस का प्रदर्शन

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में किसानों की ज्वलंत समस्याओं तथा 9 सूत्रीय मांग को लेकर कलेक्ट्रेट बेमेतरा का महापेराव एवं प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान, कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा सरकार के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। इस कार्यक्रम में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छबड़ा सहित छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे पूर्व संसदीय सचिव गुरुद्वारा बंजारे सहित जिले के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि डबल इंजन सरकार आज किसानों को खून के आंसू रुला रही है पूर्व कैबिनेट मंत्री ने लोगों के समक्ष खाद-बीज की किल्ला, डीजल-पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, सिंचाई व्यवस्था की बढहाली तथा किसानों से जुड़े अन्य मुद्दों पर प्रमुखता से बात रखी। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आशीष छबड़ा ने कहा कि भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ वादा खिलाफ़ी कर रही है किसानों को परेशान करने का काम बीजेपी

जिला किसान कांग्रेस के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन एवं कलेक्ट्रेट घेराव

एसडीएम वर्षा बंसल के समक्ष ज्ञापन के माध्यम से रखी गई 09 सूत्रीय मांग सारंगढ़ बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिला किसान कांग्रेस पार्टी सारंगढ़ के द्वारा सारंगढ़ में धरना प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन भारत माता चौक से सारंगढ़ कलेक्ट्रेट परिसर की ओर जाने और जिला कलेक्टर महोदय को किसानों को हो रही समस्याओं के अनुरूप उसके समाधान और समस्याओं को वर्तमान प्रदेश भाजपा शासित सरकार को तीखा प्रहार करने के लिए किया गया है। जिला किसान कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने इसपर बयान जारी करते हुए तथा पदेश की सरकार पर तीखा व्यंग्य करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लाखों छोटे और सीमांत किसानों की

जिला प्रशासन एवं खेल विभाग की पहल, सक्ती में आज आयोजित होगा मैराथन दौड़



सक्ती/मूक पत्रिका

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन में जिला प्रशासन एवं खेल एवं युवा कल्याण विभाग सक्ती द्वारा 12 जून 2026 को जिला मुख्यालय सक्ती में मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन सुबह 6:30 बजे सेजेस स्कूल सक्ती से



उस मर्मस्पर्शी और बढहाल स्थिति से वर्तमान प्रशासनिक अव्यवस्थाओं के कारण जुड़ रहे हैं। एक उम्मीद लेकर सोसायटियों और बाजारों की तरफ निकलता है कि शायद उसे आज खेती के लिए डीएपी (ध्रुव) खाद या ट्रैक्टर के लिए डीजल मिल जाएगा। परंतु दुर्भाग्य से शाम तक उसके बोध में सिर्फ लंबी लाइनें, धक्के, प्रशासनिक बहाने और भारी मजबूरी ही लगती हैं। जिस अन्रदाता की मेहतत से मंडियां भरती हैं, आज वही खाद के एक-एक कट्टे के लिए तरस रहा है। बड़े और रसूखदार

लोग अपनी पहचान के बल पर अपनी पूरी व्यवस्था कर लेते हैं जबकि आम और गरीब किसान पूरी तरह बेबस हो चुका है। मंत्रियों का जब भाषण देना होता है तो बड़े वादे किए जाते हैं, पर जब जमीनी स्तर पर किसान खाद, बीज और डीजल के लिए रोता है, तब पूरी प्रशासनिक व्यवस्था मौन हो जाती है। अगर किसानों की मांग समय पर पूर्ति नहीं की जाएगी तो ऐसे और प्रदर्शन करने की और प्रशासन को किसानों से माफ़ी मांगने की बात कही।

गई है।अन्रदाताओं के इसी गहरे दर्द

स्वच्छता अभियान कार्यक्रम अंतर्गत सक्ती और डभरा में चला विशेष सफाई अभियान

सक्ती/मूक पत्रिका

कलेक्टर अमृत विकास तोपनो के निर्देशन मे नगर पालिका परिषद सक्ती द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एवं स्वच्छता अभियान कार्यक्रम के तहत सुबह जिला चिकित्सालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे से शुरू हुए इस अभियान में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों तथा शहरवासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया। कार्यक्रम में नगर पालिका परिषद सक्ती अध्यक्ष श्याम सुन्दर अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ वासु जैन सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी कर्मचारी एवं शहरवासी उपस्थित रहे। सभी ने जिला चिकित्सालय परिसर में श्रमदान कर स्वच्छता का संदेश दिया तथा नागरिकों से अपने आसपास के क्षेत्रों



को साफ़-सुथरा रखने का आह्वान किया। इसी प्रकार नगर पंचायत डभरा अंतर्गत अटल परिसर पर स्वच्छता अभियान और स्वच्छता शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ समाज और जनभागीदारी में महत्व पर बल दिया गया। उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जन आंदोलन है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने और अपने

शहर व गाव को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की सहभागिता ने

यह संदेश दिया कि सक्ती जिले में स्वच्छता को लेकर जनजागरूकता लगातार बढ़ रही है और प्रशासन तथा आमजन मिलकर स्वच्छ एवं स्वस्थ समाज के निर्माण की दिशा में कार्य कर रहे हैं।

जिला चिकित्सालय परिसर में विशेष स्वच्छता अभियान के दौरान अपर कलेक्टर बॉरेंद्र लकड़ा, अपर कलेक्टर बालेश्वर राम, अपर कलेक्टर के एस पैर्रा, एसडीएम सक्ती सुश्री कावेरी मरकाम, नगर पालिका परिषद सक्ती सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने लोगों से नियमित रूप से स्वच्छता गतिविधियों में भाग लेने और अपने

कलेक्टर पद्मिनी भाई साहू ने की स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा

हार्डिस्क गर्भवती महिलाओं की सतत निगरानी और मातृ मृत्यु शून्य करने पर दिया जोर
कुष्ट रोग का पहचान एवं उपचार के लिए विशेष
जनजागरूकता अभियान
चलाने के लिए निर्देश

सारंगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

कलेक्टर पद्मिनी भाई साहू ने जिला स्तरीय स्वास्थ्य समिति की प्रथम समीक्षा बैठक लेकर जिले में संचालित स्वास्थ्य सेवाओं एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा किया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुणेन्द्र वैष्णव ने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, चिकित्सकों की संख्या, स्वास्थ्य विभाग के वाहनों की स्थिति तथा विभागीय गतिविधियों की जानकारी दी।कलेक्टर ने जिले के सभी विकासखंडों में संचालित जीवनदीप समितियों के उपलब्ध फंड की जानकारी लेकर उसका हॉस्पिटल में प्रभावी उपयोग करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिले के सभी



सर्जन चिकित्सकों को सोनेलॉजिस्ट प्रशिक्षण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए, ताकि आम नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सोनोग्राफ़े सुविधा उपलब्ध हो सके।
बैठक में जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, संस्थागत प्रसव, पूर्ण टीकाकरण सहित अन्य स्वास्थ्य सूचकांकों का समीक्षा किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर ने हार्डिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित निगरानी के लिए मितानिनें एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सक्रिय रूप से कार्य करने तथा ज़रूरतमंद महिलाओं को हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के

अधिकारियों एवं चिकित्सकों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी गर्भवती महिला की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। उन्होंने हार्डिस्क गर्भवती महिलाओं की डेटवार कार्ययोजना तैयार कर नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। बैठक में महतारी एक्सप्रेस वाहनों की उपलब्धता, संचालन एवं वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई। साथ ही फ़ाइलरिया, डेंगू, लिम्फोडेमा, टीबी एवं कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कुष्ठ रोग की पहचान एवं उपचार के लिए विशेष जनजागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिए गए। कलेक्टर ने आयुष्मान भारत एवं आयुष्मान आरोग्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए लाभान्वित हितग्राहियों की संख्या तथा शेष पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण की प्रगति की जानकारी ली और अभियान चलाकर शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए। बैठक में डिप्टी कलेक्टर शिखा शर्मा, सिविल सर्जन दीपक जायसवाल, बीएमओ, डीपीएम तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

नो-एंट्री' में खाकी का 'वसूली सिंडिकेट', बनोरा आश्रम और नालंदा परिसर के नाम पर खाली ट्रकों की भी एंट्री, 300-500 रुपये में बिक रहे नियम!



वायरल हो रही एक खबर ने रायगढ़ पुलिस महकमे की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि रायगढ़ ट्रैफ़िक पुलिस और जूटमिल थाने के कुछ जवान रात के अंधेरे में शहर के प्रतिष्ठित बनोरा आश्रम और नालंद परिसर का नाम लेकर लाखों रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं।

समय से पहले ही खुल जाते हैं नो-एंट्री के बैरिकेड्स..शहर की सुरक्षा के लिहाज से भारी वाहनों का प्रवेश रात 10 बजे से लेकर तड़के 3

बजे तक पूरी तरह से वर्जित रहता है। लेकिन वायरल हो रही खबर के मुताबिक, जूटमिल पुलिस के आरक्षक तरुण माहिलाने और ट्रैफ़िक पुलिस के जवानों द्वारा रात 11:30 बजे से ही पैसों की खातिर भारी वाहनों को शहर में घुसने की खुली छूट दे दी जाती है। आरोप है कि प्रति गाड़ी महज 300 से 500 रुपये लेकर बेखौफ़ होकर ट्रकों को शहर की ओर रवाना किया जा रहा है।

आश्रम का नाम लेकर खाली ट्रकों को भी मिल रही एंट्री..इस पूरे वसूली कांड में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब भी कोई राहगीर या मोडियकर्मई इन जवानों से नो-एंट्री के समय गाड़ियां छोड़ने का कारण

पूछता है, तो उनका रटा-रटया जवाब होता है कि इन गाड़ियों में 'बनोरा आश्रम और नालंदा परिसर का सामान' जा रहा है। यहां सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि पुलिस खाली ट्रकों और डंपरों को भी इन्हीं संस्थाओं का नाम लेकर छोड़ रही है। आखिर खाली गाड़ी में किस आश्रम का कौन सा माल ढोया जा रहा है?

आस्था के केंद्रों की छवि धूमिल करने का प्रयास..बनोरा आश्रम और नालंद परिसर जैसी संस्थाएं शहर में आस्था और सम्मान का प्रतीक हैं।

शिखा और धर्म के इन केंद्रों का नाम ढाल बनाकर जिस तरह से यह वसूली सिंडिकेट चलाया जा रहा है, वह बेहद निंदनीय है। यह न केवल प्रशासनिक नियमों की सर्राआम धज्जियां उड़ाता है, बल्कि इन पवित्र

संस्थाओं की छवि को भी बदनाम करने की एक धिंमैनी साजिश प्रतीत होती है।

एसपी से सख्त कार्रवाई की मांग..व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैल रही यह ब्रेकिंग न्यूज़ अब शहरवासियों के बीच चर्चा का प्रमुख विषय बन गई है।

जनता में इस भ्रष्टाचार को लेकर भारी आक्रोश है। अब शहर के प्रबुद्ध नागरिकों और सामाजिक संगठनों की निगाहें जिले के पुलिस अधीक्षक पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि इस वायरल दावे पर संज्ञान लेते हुए आला अधिकारी आरोपी आरक्षक तरुण माहिलाने और लिप्त ट्रैफ़िक जवानों पर क्या दंडात्मक कार्रवाई करते हैं, या फिर वर्दी की आड़ में चल रहा यह लाखों की वसूली का खेल यूं ही बेखौफ़ जारी रहेगा।

उर्वरक नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई, साहू कृषि केन्द्र का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित

बेमेतरा/मूक पत्रिका

किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा उर्वरकों की कालाबाजारी, तस्करी, डायवर्सन, जमाखोरी, अधिक मूल्य पर विक्रय, अमानक एवं नकली उर्वरकों के विक्रय पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग द्वारा जिले में लगातार निरीक्षण एवं निगरानी की कार्रवाई की जा रही है। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार गठित जिला स्तरीय निरीक्षण दल द्वारा 06 जून 2026 को विकासखंड बेमेतरा अंतर्गत ग्राम जेवरी स्थित मेसर्स साहू कृषि केन्द्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रतिष्ठान की ओर से प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किए जाने पर उसे



संतोषजनक नहीं पाया गया। इसके पश्चात उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक संचालक कृषि डॉ. श्याम लाल द्वारा संबंधित प्रतिष्ठान के उर्वरक प्राधिकार पत्र के निलंबन की अनुशंसा की गई। अनुशंसा के आधार पर प्राधिकृत अधिकारी एवं उप संचालक कृषि, बेमेतरा श्री मोरेश्वज डड्डेसा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 31(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स साहू कृषि केन्द्र, ग्राम जेवरी, विकासखंड बेमेतरा के उर्वरक प्राधिकार पत्र को 15 दिवस के लिए

निलंबित कर दिया गया है।निलंबन अवधि के दौरान संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा उर्वरकों के भंडारण एवं विक्रय से संबंधित किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि संचालित नहीं की जा सकेगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों की सुरक्षा तथा उर्वरकों के वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिले में निरीक्षण एवं प्रवर्तन की कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

सफलता की कहानी: उन्नत तकनीक से बढ़ा किसानों का विश्वास

ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम : अमरसिंह साहू और चंद्रकुमार कुंभकार बने प्रेरणा स्रोत

बेमेतरा/मूक पत्रिका

कृषि प्रधान जिले बेमेतरा में ँमिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस+ योजना के तहत ग्रीष्मकालीन उड़द एवं मूंग की खेती किसानों के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल रही है। कृषि विभाग के मार्गदर्शन, उन्नत बीजों की उपलब्धता तथा वैज्ञानिक खेती की तकनीकों के कारण जिले में इस वर्ष ग्रीष्मकालीन दलहन खेती का रकबा उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। जहां पिछले वर्ष केवल 285 हेक्टेयर क्षेत्र में उड़द-मूंग की खेती की गई थी, वहीं इस वर्ष यह बढ़कर 1191 हेक्टेयर तक पहुंच गई है। इसमें लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्र में 1280 किसानों द्वारा ग्रीष्मकालीन उड़द का प्रदर्शन किया गया, जिससे किसानों को नई तकनीकों को सीखने और अपनाने का अवसर मिला। इस सकारात्मक परिवर्तन की कहानी ग्राम गाड़ाभाउ के कृषक श्री अमरसिंह साहू तथा ग्राम बिजागोंड के कृषक श्री चंद्रकुमार कुंभकार जैसे प्रगतिशील किसानों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने पहली बार



ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती का उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं।

उन्नत तकनीक से बढ़ा किसानों का विश्वास-विकासखंड साजा के ग्राम गाड़ाभाउ निवासी कृषक श्री अमरसिंह साहू ने कृषि विभाग के मार्गदर्शन में लगभग 1.5 एकड़ भूमि में ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती की। उन्हें विभाग द्वारा उन्नत किस्म के बीज उपलब्ध कराए गए तथा कतार पद्धति से बुवाई, समय पर सिंचाई और समुचित



पोषण प्रबंधन की जानकारी दी गई। 21 अप्रैल 2026 को की गई बुवाई के बाद फसल की बढ़वार अत्यंत संतोषजनक रही। वर्तमान में उनकी फसल अच्छी स्थिति में है तथा लगभग 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन प्राप्त होने की संभावना है। श्री अमरसिंह साहू बताते हैं कि पहले वे केवल परंपरागत फसलों पर निर्भर रहते थे, लेकिन कृषि विभाग की सलाह और प्रदर्शन कार्यक्रम को देखकर उन्होंने ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती

तरीके से खेती करने और कृषि विभाग के नियमित तकनीकी मार्गदर्शन का लाभ उन्हें मिला। उनकी फसल वर्तमान में स्वस्थ एवं घनी अवस्था में है तथा 8 से 9 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन मिलने का अनुमान है। श्री चंद्रकुमार का कहना है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में उड़द की खेती को लेकर प्रारंभ में कुछ संदेह थे, लेकिन विभागीय अधिकारियों के सहयोग और सफल प्रदर्शन को देखकर उनका आत्मविश्वास बढ़ा। अब वे अपने गांव के अन्य किसानों को भी दलहन फसलों की खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

आय वृद्धि के साथ मृदा स्वास्थ्य में सुधार-ग्रीष्मकालीन उड़द की खेती केवल आर्थिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और मृदा स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी सिद्ध हो रही है। दलहन फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती हैं। इससे आगामी फसलों के लिए भूमि अधिक उपजाऊ बनती है तथा रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम होती है। यदि समय पर वर्षा हो जाए तो इन फसलों का उपयोग हरी खाद के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे

भूमि की गुणवत्ता और बेहतर होती है।

किसानों के लिए प्रेरणादायक उदाहरण-श्री अमरसिंह साहू और श्री चंद्रकुमार कुंभकार की सफलता यह साबित करती है कि यदि किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त बीज, वैज्ञानिक तकनीक और विभागीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए तो वे नई फसलों को अपनाकर बेहतर उत्पादन और आय अर्जित कर सकते हैं।

इन दोनों किसानों ने यह दिखाया है कि ग्रीष्मकालीन मौसम में भी दलहन फसलों की सफल खेती संभव है और यह खेती किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। बेमेतरा जिले में ग्रीष्मकालीन उड़द की बढ़ती खेती आत्मनिर्भर कृषि की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह पहल किसानों की आय बढ़ाने, मृदा स्वास्थ्य सुधारने तथा टिकाऊ कृषि प्रणाली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। अमरसिंह साहू और चंद्रकुमार कुंभकार जैसे किसानों की सफलता अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा बन रही है और जिले में दलहन उत्पादन के नए आयाम स्थापित कर रही है।

संपादकीय

एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच युद्धविराम की उम्मीद बंधती है और फिर टूट जाती है। यह स्थिति युद्ध शुरू होने के बाद से ही जारी है। पिछले तीन महीने से युद्ध चल रहा है, लेकिन जब शांति वार्ता की बात आती है,

तो आमने-सामने और दूरगामी स्थितियों को ध्यान में रखकर संवाद करने की जरूरत नहीं समझी जाती। अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत किसी सहमति के बिंदु पर नहीं पहुंच रही, तो इसे समझने की जरूरत है। दोनों पक्ष जिस तरह अपनी शर्तों पर अड़े हैं, उससे वैश्विक शांति को तो खतरा है ही, दुनिया भर में ऊर्जा संकट भी गहरा रहा है। गौरतलब है कि ईरान

ईरान-अमेरिका-वार्ता के साथ सैन्य दबाव, शांति की राह में सबसे बड़ी बाधा

ने अमेरिका के साथ चल रही अप्रत्यक्ष वार्ता स्थगित कर दी है। उसने क्षेत्रीय तनाव बढ़ने पर यह कदम उठाया है। यह निराशाजनक ही है कि एक तरफ कूटनीतिक कदम उठाने की बात की जाती है, फिर अचानक हमले की स्थिति पैदा कर दी जाती है। पिछले सप्ताह के आखिर में भी अमेरिका ने ईरान के भीतर कई ठिकानों पर बमबारी की। इसके अलावा, लेबनान पर

इजराइल के लगातार हमलों से ईरान नाराज है और वह चाहता है कि ये हमले रोक दिए जाएं। हालांकि यह मुद्दा युद्धविराम की मुख्य शर्तों में शामिल है। मगर सवाल है कि अमेरिका युद्धविराम को ताक पर रखकर खुद को या इजराइल को हमले करने से क्यों नहीं रोक पा रहा है। इसमें दोराय नहीं कि अगर दोनों पक्ष गंभीरता से कूटनीतिक पहल करते, तो शांति का कोई रास्ता निकल

सकता था। मगर जैसे ही बात आगे बढ़ती है, उसमें दबाव बढ़ाने के साथ रणनीतिक शर्तें जोड़ दी जाती हैं। इससे संवाद के पुल गिर जाते हैं। मौजूदा स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान ने होर्मुज जलमार्ग पर अपना दबदबा बढ़ाने और उसे सख्ती से बंद करने का संकेत दिया है। समझौते की कवायद कई दिनों से चल रही है, लेकिन कोई सार्थक परिणाम

नहीं निकल रहा, तो आखिर इसकी क्या वजह है। स्पष्ट है कि एक तरफ समझौते की बात की जाती है, दूसरी ओर सैन्य विकल्प चुनने की धमकी दी जाती है। इस द्वंद्व के बीच शांति कायम होने के सभी दावे धरे रह जाते हैं। बेहतर हो कि अमेरिका और ईरान स्थायी युद्धविराम और शांति की ओर कदम बढ़ाएं। सैन्य टकराव से आखिरकार कोई समस्या हल नहीं होती।

वर्ष 2017 में लागू जीएसटी को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में माना जाता है। अनेक अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को मजबूत किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर आधार विस्तृत हुआ और राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित बना। **दिव्य भास्कर** के अनुसार भारत का जीडीपी वर्ष 2014 के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि इकानामी सर्वे 2025-26 ने एफबाय 26 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है। कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना।

परिवर्तन के 12 वर्ष- विकास, विरासत और वैश्विक नेतृत्व



(डॉ. शिवानी कटारा)

डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले दशक में भारत की आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को व्यापक रूप से बदल दिया। भीम ऐप, आधार और यूपीआई जैसी पहलों ने भारत को डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया, जहाँ आज विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होते हैं। पिछले 12 वर्षों में भारत ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक परिवर्तनों का एक नया युग देखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास ने केवल गति ही नहीं, बल्कि नई दिशा और नई चेतना भी प्राप्त की। आर्थिक सुधारों से लेकर डिजिटल क्रांति, राष्ट्रीय सुरक्षा से सामाजिक समावेशन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण तक भारत ने आत्मनिर्भरता, सुरासन और वैश्विक प्रतिष्ठा की ओर उल्लेखनीय यात्रा तय की है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ प्रारंभ हुई यह यात्रा आज विकसित भारत 2047 के व्यापक राष्ट्रीय संकल्प में रूपांतरित होती दिखाई देती है।

आर्थिक सुधार और वित्तीय समावेशन - मोदी सरकार की शुरुआती और सबसे महत्वाकांक्षी पहलों में वर्ष 2014 का मेक इन इंडिया अभियान प्रमुख रहा, जिसने भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने की दिशा प्रदान की। घरेलू उत्पादन, विदेशी निवेश और सरल

नियमों के कारण इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा निर्माण और मोबाइल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। इससे रोजगार और औद्योगिक विकास को नई गति मिली।

इसी दौरान अंत्योदय के संकल्प के तहत आर्थिक समावेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्ष 2015 में शुरू हुई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने छोटे उद्यमियों, महिलाओं और युवाओं को बिना गारंटी ऋण उपलब्ध करारकर स्वरोजगार और ग्रामीण उत्पादों को नई पहचान दी। 6.3 करोड़ से अधिक एमएसएमई उद्यमों को सहायता मिली। वहीं, जन धन योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए, जिनमें 30.80 करोड़ खाते महिलाओं के नाम हैं। 36.73 करोड़ ग्रामीण खातों के साथ यह दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन अभियान बना।

वर्ष 2017 में लागू जीएसटी को स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े कर सुधारों में माना जाता है। अनेक अप्रत्यक्ष करों को हटाकर एक राष्ट्र, एक कर की अवधारणा को मजबूत किया गया, जिससे पारदर्शिता बढ़ी, कर आधार विस्तृत हुआ और राजस्व संग्रह अधिक व्यवस्थित बना। दृष्टिक के अनुसार भारत का जीडीपी वर्ष 2014 के लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर से बढ़कर 2025 में 4.18 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। भारत जापान को पीछे छोड़ विश्व की चौथी सबसे बड़ी

अर्थव्यवस्था बन चुका है, जबकि इकानामी सर्वे 2025-26 ने एफबाय 26 में 7.4 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान जताया है।

कोविड के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान आर्थिक रणनीति का केंद्र बना। पीएलआई योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा, टेलीकॉम और ऑटोमोबाइल सहित 14 रणनीतिक क्षेत्रों को बढ़ावा मिला, जिससे 5.31 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निर्यात हुआ। ईजी आफ इंडिंग बिजनेस, जीएसटी सुधार और डिजिटल पारदर्शिता के कारण 2025-26 में रिकॉर्ड 94.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। वहीं, नोटबंदी ने अल्पकालिक चुनौतियों के बावजूद डिजिटल भुगतान, औपचारिक अर्थव्यवस्था तथा काले धन, नकली मुद्रा और अतंक वित्तपोषण पर रोक लगाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। वहीं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना ने सरकारी संघवाद, तकनीक-आधारित शासन और प्रशासनिक दक्षता को नई मजबूती प्रदान की।

डिजिटल इंडिया, सामाजिक सशक्तिकरण और आधारभूत विकास - डिजिटल इंडिया अभियान ने पिछले दशक में भारत की आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को व्यापक रूप से बदल दिया। भीम ऐप, आधार और यूपीआई जैसी पहलों ने भारत को

डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व दिलाया, जहाँ आज विश्व के लगभग 49 प्रतिशत रियल-टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत में होते हैं। पीआई कई देशों में सक्रिय है, जबकि आईएमपीएस और फास्टटैग ने डिजिटल अर्थव्यवस्था को और गति दी। डीबीटी ऑनलाइन सेवाओं और डिजिटल पारदर्शिता ने सरकारी योजनाओं में लीकेज कम किए तथा लाभार्थियों तक सहायता सीधे पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त किया। स्टार्टअप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों ने उद्यमिता को नई ऊर्जा प्रदान की। इन योजनाओं ने युवाओं, महिलाओं और वंचित वर्गों को रोजगार खोजने वालों से रोजगार सृजित करने वालों में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ने पारंपरिक कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और डिजिटल बाजार से जोड़कर नई पहचान प्रदान की।

सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में स्वच्छ भारत अभियान के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जबकि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 50 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध हुई। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान ने बालिका शिक्षा, सुरक्षा और जागरूकता को राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप दिया। वहीं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने करोड़ों गरीब महिलाओं को धुएँ से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन, बेहतर स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन की नई दिशा दी। तीन तलाक़ प्रथा पर रोक लगाकर मुस्लिम महिलाओं को समानता, सम्मान और संवैधानिक अधिकारों की नई सुरक्षा प्रदान की गई।

कृषि क्षेत्र में पीएम किसान योजना के माध्यम से 11 करोड़ किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की प्रत्यक्ष सहायता दी गई। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में पीएम गति शक्ति योजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 3.5 लाख किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें तथा तीव्र गति से विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों ने देश की कनेक्टिविटी को नई ऊँचाइयाँ प्रदान कीं। नए हवाई अड्डों के निर्माण और 'उड़ान' योजना ने देश की हवाई कनेक्टिविटी का अभूतपूर्व विस्तार किया, जबकि वंदे भारत और तेजस जैसी आधुनिक ट्रेनों ने भारतीय रेल के आधुनिकीकरण को नई गति दी।

शिक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद 1,200 से अधिक नए विश्वविद्यालय, 10 नए आईआईटी तथा 7 नए आईआइएम स्थापित किए गए। वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान कर सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार किया गया, जिससे आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को शिक्षा और रोजगार में नए अवसर प्राप्त हुए।

नई शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक व्यावहारिक, कौशल-आधारित और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया। स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से युवाओं को उद्योग आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। वर्ष 2025 तक 2.27 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। एआई, डजी, डीन, साइबर सुरक्षा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में 400 से अधिक आधुनिक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए। इंडिया आई मिशन और सेमीकंडक्टर मिशन ने भारत को भविष्य की प्रौद्योगिकियों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार किया।

(कमलेश पांडे)

जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी।

राहुल गांधी की आर्थिक सुनामी वाली चेतावनी को फिलहाल एक राजनीतिक चेतावनी और आर्थिक जोखिमों पर विपक्षी आक्रमण के रूप में देखा जाना चाहिए। क्योंकि उनका यह कहना कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक सुनामी की ओर बढ़ रहा है, अभी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। हालांकि वैश्विक परिस्थितियों और घरेलू आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए इस बहस को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता।

आर्थिक मामलों के जानकार बताते हैं कि भारत में वास्तव में आर्थिक सुनामी आणी या नहीं, इसका कोई निश्चित उत्तर अभी नहीं दिया जा सकता। लेकिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा हाल में दी गई चेतावनी ने आर्थिक और राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी का तर्क है कि वैश्विक संकट, विशेषकर पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, महंगाई, ईंधन कीमतों और आर्थिक असमानता के कारण भारत एक बड़े आर्थिक झटके की ओर बढ़ सकता है। दूसरी ओर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा का कहना है कि भारत की अर्थव्यवस्था के पास पर्याप्त शॉक एब्जॉर्बर हैं-विदेशी मुद्रा भंडार, नियंत्रित महंगाई, खाद्यान्न भंडार, डिजिटल अर्थव्यवस्था और मजबूत कर-संग्रह जैसी व्यवस्थाएं-जो बाहरी संकटों का सामना करने में सक्षम हैं।

सवाल है कि क्या समुच्च आर्थिक संकट का खतरा है?- भारत के सामने कुछ वास्तविक चुनौतियाँ हैं- जैसे वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि की आशंका। निर्यात और निवेश पर अंतरराष्ट्रीय तनाव का असर। रोजगार सृजन की चुनौती। और कृषि और एमएसएमई क्षेत्र पर दबाव। लेकिन साथ ही भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है, और कई आर्थिक संकेतक अभी व्यापक संकट की पुष्टि नहीं करते।

जानकार बताते हैं कि आर्थिक सुनामी कोई औपचारिक आर्थिक शब्द नहीं है, बल्कि ऐसी स्थिति को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जब अर्थव्यवस्था को अचानक और व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव

और महंगाई का बढ़ना। निवेश और उपभोग में तीव्र कमी। इतिहास में ग्रेट डीप्रेसन (1930 का दशक) और ग्लोबल फायनेंस क्राइस (2008) जैसी घटनाओं को आर्थिक सुनामी के उदाहरण माना जा सकता है।

सवाल है कि क्या भारत में पीएम मोदी के रहते यह आ सकती है?- किसी भी सरकार या प्रधानमंत्री के रहते हुए आर्थिक संकट की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। अर्थव्यवस्था अनेक घरेलू और वैश्विक कारकों से प्रभावित होती है, जैसे- वैश्विक मंदी या वित्तीय संकट। तेल की कीमतों में असाधारण वृद्धि बड़े युद्ध या भू-राजनीतिक तनाव। प्राकृतिक आपदाएं या महामारी। घरेलू नीति संबंधी गंभीर त्रुटियाँ। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें भी हैं जो बड़े झटकों को सहने में मदद करती हैं- जैसे- विशाल घरेलू बाजार। अपेक्षाकृत मजबूत बैंकिंग और नियामक व्यवस्था। बढ़ता डिजिटल भुगतान तंत्र। बुनियादी ढांचे और विनिर्माण पर निवेश। विदेशी मुद्रा भंडार का पर्याप्त स्तर। दूसरी ओर, चुनौतियाँ भी मौजूद हैं-जैसे- युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार सृजन। कृषि आय में सुधार। निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता। और, आय असमानता और उपभोग मांग का प्रश्न।

इसलिए निष्पक्ष रूप से कहा जाए तो पीएम मोदी के रहते आर्थिक सुनामी निश्चित रूप से आणी या कभी नहीं आणी- दोनों दावे तथ्यात्मक रूप से सिद्ध नहीं हैं। भारत की आर्थिक स्थिति कई संकेतकों पर अपेक्षाकृत मजबूत दिखती है, लेकिन किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह यह वैश्विक और घरेलू जोखिमों से पूरी तरह मुक्त नहीं है। आर्थिक सुनामी की संभावना मुख्यतः नीतियों, वैश्विक परिस्थितियों और भविष्य की घटनाओं पर निर्भर करेगी, न कि केवल किसी एक नेता की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर।

आखिर आर्थिक सुनामी के मायने क्या हैं? - आर्थिक सुनामी एक रूपक है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यापक और तीव्र आर्थिक संकट जो समाज, बाजार, उद्योग, रोजगार और सरकार की वित्तीय स्थिति को एक साथ प्रभावित कर दे। जिस प्रकार समुद्री सुनामी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को झकझोर देती है, उसी प्रकार आर्थिक सुनामी भी अर्थव्यवस्था के लगभग सभी क्षेत्रों पर गहरा असर डालती है।

आइए जानते हैं आर्थिक सुनामी के प्रमुख संकेत के बारे में- पहला, शेयर बाजार में भारी गिरावट। दूसरा, निवेशकों की संपत्ति तेजी से घटती है। तीसरा, कंपनियों का बाजार मूल्य व्यापक झटका लगे तथा उसके प्रभाव दूरगामी हों। इसके कुछ संकेत हो सकते हैं- जीडीपी वृद्धि दर में तेज गिरावट। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी। बैंकिंग या वित्तीय संकट। शेयर बाजार में भारी गिरावट। मुद्रा पर दबाव

अन्नामलाई का नई पार्टी बनाने का निर्णय आवेश में लिया गया फैसला नहीं, लंबे चिंतन का नतीजा है

(नीरज कुमार दुबे)

तमिलनाडु की राजनीति में एक

नया भूचाल उस समय आ गया

जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व

प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई ने

पार्टी से इस्तीफा देकर अपने नए

राजनीतिक आंदोलन की

घोषणा कर दी। यह फैसला

तमिलनाडु की जमी हुई

राजनीतिक संस्कृति को चुनौती

देने वाला एक बड़ा संदेश है।

अन्नामलाई ने जिस साफगोई,

साहस और वैचारिक दृढ़ता के

साथ अपने फैसले को सामने

रखा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया

है कि वह अब किसी दल के

सीमित दायरे में नहीं, बल्कि

तमिल समाज की व्यापक

आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप

में उभरना चाहते हैं।

अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय हैं या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है। तमिलनाडु की राजनीति में एक नया भूचाल उस समय आ गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी से इस्तीफा देकर अपने नए राजनीतिक आंदोलन की घोषणा कर दी। यह फैसला तमिलनाडु की जमी हुई राजनीतिक संस्कृति को चुनौती देने वाला एक बड़ा संदेश है। अन्नामलाई ने जिस साफगोई, साहस और वैचारिक दृढ़ता के साथ अपने फैसले को सामने रखा है, उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अब किसी दल के सीमित दायरे में नहीं, बल्कि तमिल समाज की व्यापक आकांक्षाओं के प्रतिनिधि के रूप में उभरना चाहते हैं।

अन्नामलाई ने खुलकर कहा कि उनके भीतर लंबे समय से यह संघर्ष चल रहा था कि वह पहले भारतीय हैं या तमिल। यह बयान केवल भावनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति के उस मूल द्वंद्व को सामने लाता है जिसमें राष्ट्रीय दलों को अक्सर क्षेत्रीय अस्मिता के सामने संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि चार दिसंबर 2025 को ही उन्होंने पार्टी नेतृत्व को इस्तीफा का फैसला बता दिया था, लेकिन उनसे चुनाव तक रुकने का अनुरोध किया गया। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनकी लोकप्रियता और प्रभाव को लेकर कितना सजग था।

इसे भी पढ़ें- जिसने आज तक नहीं जीता कोई चुनाव, तमिलनाडु में विजय से ज्यादा वो चर्चा में क्यों? अन्नामलाई का गेम और शाह का प्लान, पूरी कहानी कुछ और है। पूर्व पुलिस अधिकारी रहे अन्नामलाई ने भारतीय जनता पार्टी में सकारात्मक बदलाव के उद्देश्य से प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने कभी तमिलनाडु की पहचान से समझौता नहीं किया। पिछले अवरह महीने में संगठनात्मक मामलों को लेकर उनकी असहमति लगातार बढ़ती गई। यही कारण है कि उन्होंने अब एक स्वतंत्र राजनीतिक रास्ता चुनने का फैसला किया है। यह निर्णय किसी आवेश का परिणाम नहीं,

बल्कि लंबे चिंतन और रणनीतिक तैयारी का हिस्सा दिखाई देता है।

अन्नामलाई ने अपने नए आंदोलन वी द लीडर की घोषणा करते हुए साफ कर दिया कि उनका उद्देश्य केवल एक और राजनीतिक दल खड़ा करना नहीं, बल्कि राजनीति की भाषा और संस्कृति को बदलना है। उन्होंने परिवारवाद और व्यक्तिपूजा की राजनीति पर सीधा हमला बोलेते हुए कहा कि किसी भी विधायक,



सांसद या मंत्री का पद स्थायी नहीं होना चाहिए। यह बयान तमिलनाडु की उस परंपरागत राजनीति पर करारा प्रहार है जिसमें कुछ परिवारों और सीमित चهرों के इर्दगिर्द सत्ता घूमती रही है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्नामलाई ने राजनीति में तकनीकी विशेषज्ञों, युवाओं और सामान्य नागरिकों की भागीदारी पर जोर दिया है। उन्होंने युवाओं से राजनीति में आने की अपील करते हुए कहा कि अब आम आदमी की नई पीढ़ी की राजनीति की नींव रखी जा रही है। यह सोच उन्हें पारंपरिक नेताओं से अलग करती है। देखा जाये तो तमिलनाडु में जहां लंबे समय से

भावनात्मक नारों और जातीय समीकरणों के आधार पर राजनीति चलती रही है, वहां अन्नामलाई प्रशासनिक दक्षता, नैतिकता और प्रतिभा आधारित नेतृत्व की बात कर रहे हैं। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।

उनके आंदोलन के अंतर्गत कोयंबटूर में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर फोर एथिक्स एंड पॉलिटिक्स की स्थापना का फैसला भी बताता है कि वह केवल चुनावी राजनीति नहीं, बल्कि

वैचारिक और नैतिक प्रशिक्षण की स्थायी व्यवस्था खड़ी करना चाहते हैं। यह दृष्टिकोण तमिलनाडु की राजनीति में एक नई बौद्धिक धारा पैदा कर सकता है। उनके आह्वान के कुछ ही समय बाद हजारों लोगों का उनके राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना यह संकेत देता है कि जनता के एक हिस्से में बदलाव की बेचैनी पहले से मौजूद थी।

बताया जा रहा है कि अन्नामलाई ने भाजपा नेतृत्व के सामने दो स्पष्ट विकल्प रखे थे। एक तो उन्हें पर्याप्त स्वायत्तता और अधिकारों के साथ कम से कम सात वर्षों तक प्रदेश नेतृत्व दिया जाए, या

फिर उन्हें स्वतंत्र राजनीतिक राह चुनने दी जाए। यह मांग उनके आत्मविकास और दृढ़दृष्टि दोनों को दर्शाती है। साथ ही इस्तीफा का ऐलान करने से पहले दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात तथा पार्टी नेतृत्व द्वारा उन्हें मनाने की कोशिश इस बात का प्रमाण है कि अन्नामलाई की वैध तमिलनाडु की मौजूदा राजनीति भी अन्नामलाई के लिए

अवसर लेकर आई है। हालांकि विधानसभा चुनावों में द्रविड दलों को झटके लगे और अभिनेता विजय की पार्टी ने अप्रत्याशित सफलता हासिल की। इससे यह स्पष्ट हो गया कि राज्य की जनता अब पारंपरिक राजनीतिक ढांचे से बाहर विकल्प तलाश रही है। अन्नामलाई का मानना है कि राष्ट्रीय दलों के लिए यहां सीमित राजनीतिक जगह है, इसलिए एक मजबूत क्षेत्रीय विकल्प ही जनता की आकांक्षाओं को सही दिशा दे सकता है। उनकी यह समझ राजनीतिक रूप से बेहद व्यावहारिक और दूरदर्शी मानी जा रही है।

उभर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने भले ही कहा हो कि अन्नामलाई के जाने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन राजनीतिक वास्तविकता इससे अलग दिखाई देती है। अन्नामलाई ने तमिलनाडु में भाजपा को ऊर्जा, आक्रामकता और जनस्वीकार्यता दी थी। अब उनके अलग होने से भाजपा के सामने नेतृत्व और जनधार दोनो की चुनौती खड़ी होगी। दूसरी ओर, अन्नामलाई यदि अपने आंदोलन को संगठित ढंग से आगे बढ़ाते हैं तो वह तमिलनाडु की राजनीति में तीसरी शक्ति के रूप में तेजी से उभर सकते हैं।

बहरहाल, यह स्पष्ट है कि अन्नामलाई ने केवल पार्टी नहीं छोड़ी, बल्कि तमिलनाडु की राजनीति को नई दिशा देने की चुनौती स्वीकार की है। उनकी राजनीति में साहस है, वैचारिक स्पष्टता है और बदलाव की बेचैनी भी है। आने वाले वर्षों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या उनका यह आंदोलन तमिलनाडु की राजनीति में वैसा ही परिवर्तन ला पाएगा जिसकी वह कल्पना कर रहे हैं। फिलहाल इतना तय है कि अन्नामलाई ने राजनीति के मैदान में एक नई बहस छेड़ दी है और इस बहस को नजरअंदाज कर पाना किसी के लिए आसान नहीं होगा। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

सैमसंग ने ‘द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट’ की घोषणा की, घरेलू उपकरणों पर आकर्षक समर ऑफर्स

गुरुग्राम: सैमसंग इंडिया ने ‘द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट’ की घोषणा की है, जो 12 जून से 19 जुलाई 2026 तक चलेगा। इस दौरान कंपनी अपने बिस्पोक एआई होम अप्तायंसेज पोर्टफोलियो पर आकर्षक समर ऑफर्स दे रही है। चुनिंदा बिस्पोक एआई रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर और अन्य घरेलू उपकरणों पर ग्राहकों को 20,000 रुपये तक का कैशबैक और एक्ससेंटेड वारंटी जैसे लाभ मिलेंगे, जिससे इस गर्मी में एआई-समर्थित स्मार्ट जीवनशैली अपनाना आसान होगा। ऑफ के तहत, चुनिंदा रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीदने वाले ग्राहक सैमसंग केयर+ के माध्यम से एक वर्ष की एक्ससेंटेड वारंटी खरीदकर अतिरिक्त दो वर्ष की वारंटी निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर पर ग्राहक केवल 99 रुपये में एक वर्ष की एक्ससेंटेड वारंटी का लाभ उठा सकते हैं। चुनिंदा टॉप-लोड वॉशिंग मशीनों के इंस्टॉलेशन के समय ग्राहकों को मुफ्त फिल्टर भी दिया जाएगा, जो मशीन को धूल और जंग से बचाकर उसकी आयु बढ़ाने में मदद करता है। इसके अलावा, सैमसंग फ़डनेस+ के माध्यम से खरीदारी करने पर ग्राहकों को 1000 रुपये तक का कैशबैक मिलेगा। यह पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया पर आधारित है, जिससे खरीदारी का अनुभव आसान होने के साथ इसकी पहुंच भी बढ़ती है। इसके अलावा, एयर कंडीशनर खरीदने वाले ग्राहकों को 5 वर्ष की कॉन्प्रिहेंसिव वारंटी का लाभ मिलेगा, जो उत्पाद की दीर्घकालिक विश्वसनीयता सुनिश्चित करते हुए उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त भरोसा देता है। ‘द बिग बिस्पोक एआई फेस्ट’ के ऑफ़ Samsung.com, प्रमुख ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और देशभर के चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध हैं। सैमसंग के बिस्पोक एआई अप्तायंसेज एडवांस्ड एआई और स्मार्ट कनेक्टिविटी तकनीक से लैस हैं, जो उपयोगकर्ताओं को अधिक स्मार्ट, सहज और ऊर्जा-कुशल अनुभव प्रदान करते हैं। बिस्पोक एआई एयर कंडीशनर तेज कूलिंग के साथ एयरफ्लो को स्वतः समायोजित करते हैं, जिससे लंबे समय तक आरामदायक वातावरण बना रहता है।

स्कोडा ऑटो ने भारत में बढ़ाईआरएस विरासत, नई कोडियाक आरएस एसयूवीलॉन्च करने का किया ऐलान

स्कोडा ऑटो इंडिया अपनी हाई-परफॉर्मेंस आरएस रेंज को नई कोडियाक आरएस के साथ और मजबूत करने जा रही है। 50 वर्षों से अधिक पुरानी आरएस विरासत और 125 वर्षों से ज्यादा के मोटरस्पोर्ट इतिहास पर आधारित यह नया मॉडल ब्रांड की परफॉर्मेंस-उन्मुख पहचान को और मजबूती देता है। 22 जून 2026 से बुकिंग के लिए उपलब्ध होने वाली कोडियाक आरएस दमदार परफॉर्मेंस, शानदार मोटरस्पोर्ट कैरेक्टर, सात-सीटर लगजरी की बहुउपयोगिता और 4×4 तकनीक से लैस बेहतर ऑल-टैरेन क्षमता का बेहतरीन मेल पेश करती है। इस घोषणा पर स्कोडा ऑटो इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर आशीष गुप्ता ने कहा, आरएसबैज 50 वर्षों से अधिक की वैश्विक परफॉर्मेंस विरासत का प्रतीक रहा है और भारत में भी ऑक्टाविया आरएस के दो दशक पहले आगमन के बाद से इसका बेहद मजबूत प्रशंसक वर्ग रहा है। पिछले साल लॉन्च हुई नई ऑक्टाविया आरएस केवल 20 निमट में पूरी तरह बिक गई थी, जिसने ऑटोमोबाइल उत्साहियों के बीच इसकी खास लोकप्रियता को साबित किया। अब हम इसी विरासत को कोडियाक आरएस के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यह भारत में प्रतिष्ठित आरएस बैज पाने वाली हमारी पहली सात-सीटर है और देश में अब तक की सबसे तेज़ स्कोडा थी। यह परफॉर्मेंस, स्पेस और 4×4 क्षमता को हमारी रेसिंग विरासत की दमदार पहचान के साथ पेश करती है।

कोडियाक आरएस: परफॉर्मेंस इसकी पहचान- आरएस बैज, जिसका अर्थ रैली स्पोर्ट है, स्कोडा ऑटो की परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वैश्विक स्तर पर आरएस मॉडल्स अपनी दमदार क्षमता, बेहतरीन प्रिसिजन और रोमांचक ड्राइविंग अनुभव के लिए जाने जाते हैं। कोडियाकआरएस के साथ यह दर्शन अब भारत के लगजरी एसयूवी सेगमेंट में प्रवेश कर रहा है, जो बहुउपयोगी और ऑल-टैरेन क्षमता वाले पैकेज में और भी ज्यादा शार्प तथा रोमांचक ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। कोडियाक आरएस ब्रांड की ‘डिफेंशिएशन’ रणनीति को भी दर्शाता है।

श्रीलंका के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को भेजा बधाई पत्र

कोलंबो, एंजेंसी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायका ने पीएम मोदी को एक बधाई पत्र भेजा है। यह पत्र आठ जून का है। उन्होंने लिखा कि यह रिकॉर्ड सिर्फ सरकार में बितापे साल नहीं है। यह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भरोसे का प्रतीक है। जनता ने बार-बार पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सोच ने श्रीलंका सहित कई देशों को प्रेरित किया है। भारत की ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति का श्रीलंका सबसे बड़ा गवाह रहा है। साल 2022 के आर्थिक संकट में भारत ने श्रीलंका की बहुत बड़ी मदद की थी। इसके बाद चार से छह अप्रैल 2025 को पीएम मोदी ने श्रीलंका का दौरा किया था। यह उनका वहां का चौथा दौरा था। तब उन्हें श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘मित्र विवर्ण’ से नवाजा गया था। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक व्यक्तिगत वीडियो संदेश जारी किया है। उन्होंने पीएम मोदी को नेतृत्व का रोल मॉडल बताया है। मारापे ने कहा कि 20 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालना एक चमत्कारी उपलब्धि है। उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों को

जॉर्डन ने हवा में मार गिराई ईरान की पांच मिसाइलें, तनाव बढ़ा; खाड़ी देशों में बज रहे सायरन

तेहरान/ वॉशिंगटन, एंजेंसी। अमेरिका और ईरान के बीच जारी युद्धविराम टूट गया है। सैन्य हेलिकॉप्टर को निशाना बनाए जाने के बाद अमेरिका बुरी तरह से ईरान पर भड़क गया है और अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य हमले शुरू कर दिए हैं। वहीं आईआरजीसी ने भी एक बयान जारी कर रहा है कि वे भी हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे।

कुवैत ने कहा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम सक्रिय होकर हवाई खतरों का सामना कर रहे हैं, जब ईरान ने अमेरिकी हवाई हमलों के जवाब में इस खाड़ी देश को निशाना बनाने का दावा किया। ईरान की ओर से यह कार्रवाई क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच की गई है। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। कुवैती सुरक्षा बलों ने कई प्रोजेक्टाइल को हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या हताहत की सूचना नहीं है।

जॉर्डन ने दावा किया है कि उसने ईरान की ओर से दागी गई पांच मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। ये

शी जिनपिंग का उत्तर कोरिया दौरा: सहमति का दावा बढ़ा, पर हाथ रहा खाली; नहीं हुआ कोई ठोस समझौता

बीजिंग, एंजेंसी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उत्तर कोरिया की दो दिनी यात्रा पूरी करने के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन के साथ महत्वपूर्ण सहमति पर पहुंचने के दावा किया। हालांकि, दोनों रणनीतिक सहयोगियों के बीच किसी ठोस समझौते की कोई घोषणा नहीं हुई। उत्तर कोरिया की यात्रा के पहले दिन सोमवार को जिनपिंग ने किम को चीन के अटूट समर्थन का आश्वासन दिया था। यह सात साल बाद जिनपिंग की उत्तर कोरिया की यात्रा थी। दोनों रणनीतिक सहयोगियों के बीच किसी ठोस समझौते की कोई घोषणा नहीं हुई और चीनी विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर किसी भी वार्ता से संबंधित सवालों का जवाब देने से इन्कार कर दिया। उत्तर कोरिया, जिसने 2006 से कई परमाणु परीक्षण किए हैं, सार्वजनिक रूप से खुद को परमाणु-आयुध से लैस देश बताता है, लेकिन बीजिंग कोरियाई प्रायद्वीप पर परमाणु हथियारों के विरोध में है और परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता है। उत्तर कोरिया की जिनपिंग की यात्रा के परिणामों पर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने संकेत दिया कि कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर बीजिंग के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा, चीन कोरियाई प्रायद्वीप के मुद्दे पर अपनी स्थिति और नीति में निरंतरता और स्थिरता बनाए हुए है।

पाकिस्तान के हवाई हमलों से अफगानिस्तान में 13 लोगों की मौत, 11 बच्चे भी शामिल

काबुल,एंजेंसी। अफगानिस्तान ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर उसके क्षेत्र में हवाई हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए। इन हमलों के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच पहले से चल रहा तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बुधवार को बताया कि पाकिस्तानी हवाई हमले अफगानिस्तान के खोस्त, कुनार और पक्तिका प्रांतों में किए गए। उनके अनुसार हमलों में 11 बच्चों, एक महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है।

तालिबान सरकार ने इन हमलों की कड़ी निंदा करते हुए इसे नागरिकों को निशाना बनाने वाली कार्रवाई बताया है। हालांकि पाकिस्तान की ओर से इन हमलों को लेकर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कई महीनों से सीमा पर तनाव बना हुआ है। फरवरी के अंत से दोनों देशों के बीच लगातार संघर्ष और जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है।

टीटीपी को लेकर पाकिस्तान लगाता रहा है आरोप

मिसाइलें उस क्षेत्र की ओर बढ़ रही थीं, जहां अमेरिकी सैन्य बलों की मौजूदगी वाला एयरबेस स्थित है। हमले के बाद



जॉर्डन समेत कई खाड़ी देशों में चेतावनी सायरन बजाए गए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया। रिपोर्टों के अनुसार, यह घटनाक्रम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव के बीच हुआ है। जॉर्डन ने कहा कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह सक्रिय है और देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी सेना वाले सैन्य अड्डे पर हमला किया; हालांकि, अभी तक जॉर्डन और अमेरिका की ओर से इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की गई है।

28 फरवरी से अमेरिका और इस्राइल द्वारा ईरान पर किए जा रहे हमलों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को



प्रभावित किया है। इसके चलते ऊर्जा कीमतों में तेजी आई है और खाद्य पदार्थों समेत कई आवश्यक वस्तुएं महंगी हुई हैं। हालांकि अप्रैल में युद्धविराम की घोषणा की गई थी, लेकिन अब तक स्थायी शांति समझौता नहीं हो सका है। इस बीच, इस्राइल ने लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्ला के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है, जिससे क्षेत्रीय तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यह घटना ऐसे समय हुई है जब दो महीने पुराने संघर्षविराम पर पुष्टि नहीं की गई है।

असाविधानिक और क्रूर: अलबामा में नाइट्रोजन गैस से मृत्युदंड पर स्थायी रोक, जज ने कहा- ये प्रतिबंध का उल्लंघन

मॉन्टगोमेरी, एंजेंसी। अमेरिका के अलबामा राज्य में नाइट्रोजन गैस के जरिए दी जाने वाली मौत की सजा पर बड़ा कानूनी झटका लगा है। एक संघीय न्यायाधीश ने इस तरीके को संविधान के खिलाफ और अत्यधिक क्रूर बताते हुए एक कैदी की प्रस्तावित सजा पर स्थायी रोक लगा दी है। अमेरिकी जिला न्यायाधीश एमिली सी. मार्क्स ने मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि नाइट्रोजन गैस के जरिए मौत की सजा देना संविधान में दिए गए क्रूर और असामान्य सजा पर प्रतिबंध का उल्लंघन करता है।

यह फैसला उस समय आया जब एक अपीलीय अदालत ने एक दिन पहले ही उनके पुराने फैसले को पलट दिया था, जिसमें इस पद्धति को साविधानिक माना गया था। जज मार्क्स ने कैदी जेफरी ली को नाइट्रोजन गैस से मौत की सजा देने पर स्थायी रोक लगा दी। जेफरी ली को गुरुवार को अलबामा की एक जेल में मृत्युदंड दिया जाना था। हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य चाहे तो अन्य स्वीकृत तरीकों से सजा-ए-मौत को लागू कर सकता है। अलबामा में फिलहाल घातक इंजेक्शन (लीथल इंजेक्शन) और इलेक्ट्रिक चेयर भी वैध मृत्युदंड के तरीके हैं। जज ने कहा कि

पश्चिम एशिया में फिर भड़का तनाव, ईरान का दावा- बहरीनमें अमेरिकी बेस पर किया ड्रोन हमला

तेहरान, एंजेंसी। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब खुली सैन्य कार्रवाई तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी नौसेना के फिफथ फ्लीट मुख्यालय पर ड्रोन हमला किया। इसके कुछ घंटों बाद अमेरिका ने भी जवाबी कार्रवाई की पुष्टि कर दी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने कहा कि अमेरिकी सेना ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, रडार साइट्स और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशनों पर सटीक हमला किया है। पूरे घटनाक्रम के बाद होर्मुज क्षेत्र में तनाव और बढ़ गया है। सेंटकॉम ने कहा कि एक दिन पहले अमेरिकी सेना का एएच-64 अपाचे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद यह हमला किया गया। अमेरिका का दावा है कि ईरान की ओर से क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों के लिए खतरा पैदा किया जा रहा था। इसके जवाब में अमेरिकी वायुसेना और नौसेना के लड़ाकू विमानों ने होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका ने इसे संतुलित और सीमित जवाब बताया है। ईरान के इस्लामिक रिवाल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कहा कि यह हमला अमेरिका की ओर से दक्षिणी ईरान में किए गए एयरस्ट्राइक के जवाब में किया गया। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सेना ने जास्क, सिरिक और केशम जैसे इलाकों में हमले किए, जिससे नागरिक ढांचे को नुकसान पहुंचा। आईआरजीसी के मुताबिक इन हमलों में टेलीकॉम टावर और पानी की टंकियां तबाह हुईं। इसके बाद ईरान ने शाहेद-136 ड्रोन के जरिए बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक मुख्यालय को निशाना बनाया। बहरीन में मौजूद अमेरिकी फिफथ फ्लीट पश्चिम एशिया में अमेरिका की सबसे अहम सैन्य ताकतों में से एक मानी जाती है। यह फ्लीट अरब सागर, लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के कुछ हिस्सों में अमेरिकी नौसैनिक गतिविधियों की निगरानी करती है। साथ ही तेल सप्लाई रूट और अंतरराष्ट्रीय जहाजों की सुरक्षा भी इसी के जिम्मे होती है। ऐसे में इस ठिकाने पर हमला क्षेत्रीय सुरक्षा के लिहाज से बेहद गंभीर माना जा रहा है।

जेफरी ली को इन तरीकों से फांसी रोकने का अधिकार नहीं है।



अपने 26 पन्नों के फैसले में जज मार्क्स ने कहा कि मौत की सजा के हर तरीके को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने लिखा कि अगर राज्य फायरिंग स्क्वाड को भी अपनाए तो उसके खिलाफ भी कानूनी चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने यह भी माना कि संविधान दर्दरहित मौत की गारंटी नहीं देता, लेकिन किसी व्यक्ति की जान लेने की प्रक्रिया में दर्द का जोखिम पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। दिलचस्प बात यह है कि जज ने कहा कि राज्य चाहे तो ली को पसदीदा फांसी की विधि, यानी फायरिंग स्क्वाड, को अपना सकता है।

वेस्ट बैंक संकट: इस्राइली सेटलर्स पर छह देशों का एक्शन, घिरे कैबिनेट मंत्री, फ्रांस-ब्रिटेन ने दी बड़ी चोट

पेरिस, एंजेंसी। वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। इस हिसा को लेकर दुनिया के छह बड़े देश बहुत गुस्से में हैं। इन देशों ने मिलकर हिसक इस्राइली सेटलर्स पर नए और कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस कार्रवाई में इस्राइल के एक बड़े कैबिनेट मंत्री को भी निशाना बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस कदम से इस्राइल पर दबाव बनाना चाहता है, ताकि वहां तुरंत हिंसा रोकी जा सके। इस कार्रवाई में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे और न्यूजीलैंड शामिल हैं। इन छह देशों के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि चरमपंथी सेटलर्स लगातार फलस्तीनियों पर हमले कर रहे हैं। उनके मानवाधिकारों का खुलेआम हनन हो रहा है। इन हिंसक लोगों को इस्राइल सरकार का पूरा समर्थन मिल रहा है। ये लोग बिना किसी डर के काम कर रहे हैं। सरकार की मदद से वहां नई बस्तियां बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह गलत है। फ्रांस ने इस्राइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच के अपने देश में आने पर रोक लगा दी है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने कहा कि स्मोट्रिच बस्तियों के विस्तार को बढ़ावा दे रहे हैं। वे फलस्तीनी गांवों को खाली करा रहे हैं। फ्रांस ने इसके साथ ही चार बड़े नेताओं और 21 हिंसक सेटलर्स पर भी पाबंदी लगाई है। दूसरी तरफ, ब्रिटेन ने भी बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन ने बस्तियों को पैसा देने वाले छह संगठनों पर वित्तीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब ये संयुक्त पैसों का लेन-देन नहीं कर पाएंगे। इस्राइल सरकार इस फैसले से बेहद नाराज है। इस्राइल के विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों को अपमानजनक बताया है। उनका कहना है कि इस तरह के कदमों से दुनिया में यहूदी विरोधी भावना बढ़ेगी।

अगर सुरक्षित रहना चाहते हो तो हमारे क्षेत्र से निकल जाओ, अमेरिकी हमले के बाद ईरान की खुली धमकी

तेहरान, एंजेंसी। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर वह सुरक्षित रहना चाहता है तो उसे फारस की खाड़ी क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईरान की शास्त्र सेनाएं किसी भी हमले या धमकी का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अब्बास अराघची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि युद्ध के मैदान में असफल रहने के बाद अमेरिका ने ईरान के संकल्प को परखने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान की शक्तिशाली सेना किसी भी हमले को बिना जवाब दिए नहीं छोड़ेगी। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि



मौजूद है। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिकी सेना ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू की है। अमेरिकी सेंट्रल

कमांड (सेंटकॉम) के अनुसार, अमेरिकी बलों ने ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले शुरू किए हैं। सेंटकॉम का कहना है कि यह कार्रवाई उस घटना के जवाब में की गई, जिसमें ईरान ने अमेरिकी सेना के एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया था। सेंटकॉम ने बताया कि राष्ट्रपति के निर्देश पर मंगलवार शाम से ये हमले शुरू किए गए। अमेरिकी सेना का कहना है कि यह ईरान की अनुचित आक्रामकता के खिलाफ संतुलित और सीमित जवाबी कार्रवाई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य के ऊपर गश्त कर रहे एक अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया। हालांकि उन्होंने कहा कि

हेलीकॉप्टर में मौजूद दोनों पायलट सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई है। इसके बावजूद ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया कि अमेरिका इस हमले का जवाब देगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि उन्हें सेना से जानकारी मिली है कि ईरान ने एक अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि पायलट सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका के लिए इस हमले का जवाब देना आवश्यक है। इस्राइल के बीच की तनाव बढ़ा है। दोनों देशों के बीच लगातार हमले और जवाबी हमले हो रहे हैं। रिपोर्टों के अनुसार इस्राइल ने ईरान के एक पेट्रोकेमिकल संयंत्र को निशाना बनाया, जबकि ईरान की ओर से इस्राइली सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए।

खरीफ सीजन में खाद-बीज संकट को लेकर कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, 9 सूत्रीय मांगों का झापन सौंपा

मूक पत्रिका/जांजगीर-चांपा। खरीफसीजन की शुरुआत के साथ ही किसानों को खाद, बीज, डीजल और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला किसान कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में कचहरी चौक में जोरदार धरना-प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय मांगों का झापन जिला प्रशासन को सौंपा गया।

धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया है। खरीफ सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन सहकारी समितियों में खाद और बीज का गंभीर संकट बना हुआ है। उन्होंने प्रति एकड़ केवल एक बोरी खाद देने के नियम को किसानों के साथ अन्याय बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।

जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष कमल साव काका ने कहा कि सहकारी समितियाँ किसानों की सुविधा का केंद्र बनने के बजाय परेशानी



का कारण बन गई हैं। समय पर खाद और बीज उपलब्ध नहीं होने से बोनी प्रभावित होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

पूर्व शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष रामकुमार पटेल ने कहा कि किसान सुबह से शाम तक खाद कतरों और निराशा ही मिल रही है।

वहीं पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश शर्मा

ने कहा कि ट्रैक्टर की अनिवार्यता और जरकिन में डीजल देने पर प्रतिबंध ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अशोषित बिजली कटौती से सिंचाई व्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

कांग्रेस नेताओं ने मांग की कि प्रति एकड़ एक बोरी खाद का नियम तत्काल समाप्त किया जाए, खाद वितरण की तीन किरतों वाली

व्यवस्था खत्म हो और सभी किसानों को एकमुश्त खाद उपलब्ध कराई जाए।

कार्यक्रम के दौरान गिरधारी यादव, संदीप यादव, जगदीश राठौर, किशोर साहू, लोकेश राठौर, सुनील साधवानी,पंकज शुक्ला, भगवान दास गढ़वाल, गौरव सिंह, देवकुमार पाण्डेय, राजू रतिया और भुनेश्वर साहू ने भी किसानों की समस्याओं को लेकर अपने विचार रखे।

धरना-प्रदर्शन में अकील हुसैन (प्रभारी महामंत्री-संगठन, छत्तीसगढ़ प्रदेश किसान कांग्रेस), सुनील सोनकर (प्रदेश महामंत्री), डॉ. संजय साहू (प्रदेश सचिव), हरीश पाण्डेय, दुर्गा कुरें, गोपाल गुप्तशन सोनी,अमृत लाल, रवि कुमार, जगन्नाथ यादव, मदन कहरा, किशन पटेल, रूपेश कश्यप, शीतल दास मानिकपुरी, राजा रावत सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी, किसान एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन रफीक सिद्दीकी ने किया, जबकि आधार प्रदर्शन जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष कमल साव काका ने किया।

जिस शाल वृक्ष ने दिया रोजगार उसी पर चलती है कुल्हड़ी आखिर क्यों

विडंबना : जिस जंगल से मिल रही आजीविका, उसी हरियाली को पहुंचाया जा रहा नुकसान

शाल बीज और तेंदूपत्ता से मिल रहे हजारों रुपये, फिर भी हरे-भरे वृक्षों पर चल रही कुल्हाड़ी

पवन कुमार नाग/बस्तर के जंगल आज भी हजारों ग्रामीण परिवारों की आजीविका का प्रमुख आधार बने हुए हैं। शाल बीज, तेंदूपत्ता, महुआ और अन्य लघु वनोपजों से ग्रामीणों को हर वर्ष हजारों रुपये की आमदनी प्राप्त होती है। हाल ही में कई ग्रामीणों के खातों में शाल बीज संग्रहण की राशि पहुंची है। किसी को 10 हजार रुपये मिले तो किसी को 15 हजार रुपये तक की आय प्राप्त हुई। यह राशि जंगलों की अमूल्य उपयोगिता को दर्शाती है। लेकिन इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि जिस जंगल से लोगों को



आर्थिक लाभ मिल रहा है, उसी जंगल के हरे-भरे वृक्षों को काटकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है। जिन शाल वृक्षों के कारण आज ग्रामीणों के घरों तक आय पहुंच रही है, उन्हीं वृक्षों पर कुल्हाड़ी चलाकर भविष्य की खुशहाली को खतरे में डाला जा रहा है।

ग्रामीणों को यह समझना होगा कि शाल बीज, तेंदूपत्ता और अन्य वनोपज पेड़ों के जीवित रहने पर ही प्राप्त होते हैं।

यदि आज पेड़ों की अंधाधुंध कटाई होती रही तो आने वाले वर्षों में न वनोपज बचेगी और न ही उससे मिलने वाली आय। जंगल खत्म होंगे तो रोजगार के अवसर भी समाप्त हो जाएंगे।

पर्यावरण संरक्षण केवल वन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर ग्रामीण और हर नागरिक का कर्तव्य है। एक पेड़ कटने से केवल लकड़ी का नुकसान नहीं होता, बल्कि प्रकृति, पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों का भी नुकसान होता है।

जागरूकता संदेश:-आज जो शाल बीज से हजारों रुपये मिल रहे हैं, वह जंगलों की देन है। यदि जंगल नहीं बचेगें तो न शाल बीज मिलेंगे, न तेंदूपत्ता और न ही ग्रामीणों की आय।:-

=पेड़ काटकर कुछ समय का लाभ मिल सकता है, लेकिन पेड़ बचाकर पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है।:-

=जंगल दे रहे हजारों की आमदनी, फिर भी हरे-भरे वृक्षों को पहुंचाया जा रहा नुकसान=-

संदिग्ध मौत से उठे सवाल: ओडिशा में युवक की मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, निष्पक्ष जांच की मांग

परिजनों ने कहा-आत्महत्या नहीं, सुनियोजित हत्या

दैनिक मूक पत्रिका/ विक्रम ठाकुर/कांकर:- पखांजूर पीबी-8 चाणक्यपुरी निवासी युवक अनिल बाछड़ की ओडिशा में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। परिजनों और ग्रामीणों ने मामले को आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। जानकारी के अनुसार अनिल बाछड़ प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी काम के सिलसिले में ओडिशा गया था। इसी दौरान उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का कहना है कि अनिल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आत्महत्या जैसा कदम उठाए, इसलिए

'महिला को बदनाम करने की धमकी देकर मांगे दो लाख, बांटे पुलिस ने ब्लैकमेलर को दबोचा



पखांजूर के होटल में छिपा था आरोपी, बांटे पुलिस की त्वरित कार्रवाई से चढ़ा हथ्थे

दैनिक मूक पत्रिका / विक्रम ठाकुर/कांकर:-कांकर, 10 जून थाना बांटे पुलिस ने महिला की आपत्तिजनक फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपये की मांग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी को पुलिस ने पखांजूर क्षेत्र से गिरफ्तार किया।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थिना ने 5 जून 2026 को



उसकी मौत के पीछे किसी गहरी साजिश की आशंका से इनकार नहीं किया जा

सकता। मृतक के परिजनों और क्षेत्र के ग्रामीणों ने पखांजूर पहुंचकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को झापन सौंपा। झापन में घटना की निष्पक्ष एवं गहन जांच कराने की मांग करते हुए कहा गया है कि मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता लगाया जाए तथा यदि हत्या हुई है तो दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

ग्रामीणों ने प्रशासन से अग्रदृष्टि किया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए ओडिशा प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि मृतक के परिवार को न्याय मिल सके।

मूक पत्रिका/जांजगीर-चांपा। जिले में धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास पर जांजगीर सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए इसाई चंगाई सभा के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पास्टर सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय के निर्देश पर की गई इस कार्रवाई में ग्राम उदयबंद क्षेत्र के गुड़ीपारा में आयोजित कथित चंगाई सभा का खुलासा हुआ, जहां बीमारी के इलाज और चमत्कारी पानी के नाम पर लोगों को बुलाकर इसाई धर्म का प्रचार-प्रसार किया जा रहा था तथा हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली टिप्पणियां की जा रही थीं।



प्रार्थी सतीश सोनी, जो हिंदू जागरण मंच में जिला प्रशासन संपर्क प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, ने 11 जून 2026 को सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में बताया गया कि ग्राम उदयबंद निवासी बद्रीनाथ बरेठ अपने घर में बाहर से आए पास्टर एवं अन्य लोगों को बुलाकर चंगाई सभा का आयोजन कर रहा है। इस दौरान आसपास के लोगों को बीमारी ठीक करने के बहाने बुलाया जा रहा था, चमत्कारी पानी पिलाया जा रहा

था तथा बाइबल व अन्य धार्मिक पुस्तकें वितरित की जा रही थीं। साथ ही हिंदू देवी-देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक एवं अभद्र टिप्पणियां की जा रही थीं। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए थाना सिटी कोतवाली में धारा 299 एवं 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं सीएसपी कोतवाली को दी गई, जिनके निर्देश पर पुलिस

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन



जांजगीर-चांपा। कलेक्टर जन्मेजय महोबे के निर्देशन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत 12 जून विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर विकासखंड बम्हनीडीह के ग्राम पोड़ीकला में आज बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य बाल श्रम के प्रति जनजागरूकता बढ़ाना तथा बच्चों को

कार्यक्रम एवं पोषण अभियान सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। कार्यक्रम में बताया गया कि बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रोजगार में लगाना प्रतिबंधित है तथा 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना अपराध है। बाल श्रम की किसी भी घटना की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने की अपील की गई। साथ ही लिंग समानता, बालिकाओं की शिक्षा एवं सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम के दौरान किशोरी बालिकाओं के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया तथा अंत में उपस्थित जनों को बाल श्रम रोकथाम एवं निषेध की शपथ दिलाई गई।

मूक पत्रिका/जांजगीर-चांपा। झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद वरिष्ठ कांग्रेस नेता स्व. विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी चांपा द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहादत दिवस मनाया गया। 25 मई 2013 को झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में घायल होकर देश और प्रदेश के लिए बलिदान देने वाले स्व. विद्याचरण शुक्ल की शहादत को कांग्रेसजनों ने कभी न भूलने वाला बलिदान बताया। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेश अग्रवाल द्वारा स्व. विद्याचरण शुक्ल के तैलीय चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस अवसर पर उन्होंने शुक्ल जी के राजनीतिक जीवन और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से लेकर प्रदेश को सशक्त बनाने में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ उनके बलिदान को कभी भुला नहीं सकता। पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष



दिनेश शर्मा ने भी स्व. विद्याचरण शुक्ल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके संघर्ष, दूरदर्शिता और जनसेवा को कांग्रेस की अमूल्य धरोहर बताया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सुनील साधवानी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शुक्ल जी का बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष अनिल मोदी, समद बेग, हरीश श्रीवास, लता श्रीवास, हरीश पांडेय, अनिता प्रकाश सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का संचालन ब्लॉक अध्यक्ष सुनील साधवानी ने किया, जबकि आधार

जगदलपुर में नशे के खिलाफबस्तर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 15.654 किलो गांजा के साथ भोपाल का युवक गिरफ्तार

जगदलपुर - बस्तर पुलिस द्वारा नशे के कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बोधघाट क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 15.654 किलोग्राम गांजा, एक टच स्क्रीन मोबाइल और नगदी राशि बरामद कर कुल 7 लाख 87 हजार 700 रुपये की संपत्ति जब्त की है।

पुलिस अधीक्षक श्री लालधन कुमार सिन्हा के नेतृत्व में जिले में नशे के सौदागरों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में 11 जून को थाना बोधघाट पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि नया बस स्टैंड जगदलपुर के पीछे आम के पेड़ के पास एक युवक दो काले रंग के बैग में गांजा लेकर बस का इंतजार कर रहा है।

सूचना के आधार पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग के मार्गदर्शन तथा नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार के पर्यवेक्षण में



थाना प्रभारी टामेश्वर चौहान के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर सदही युवक को पकड़ लिया।

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शुभम प्रजापति (28 वर्ष) पिता हीरालाल प्रजापति, निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से दो बैगों में रखा 15.654 किलोग्राम गांजा, एक पुराना रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन तथा 500 रुपये नकद बरामद किए गए।

आरोपी गांजा रखने एवं परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर

सका। इसके बाद पुलिस ने मादक पदार्थ को जब्त कर आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (द्वंद्व) (बी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर विशेष एनडीपीएस न्यायालय जगदलपुर में पेश किया गया।

कार्रवाई में शामिल पुलिस टीम- इस टीम ने मौके पर घेराबंदी कर सदही युवक को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम शुभम प्रजापति (28 वर्ष) पिता हीरालाल प्रजापति, निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) बताया। तलाशी लेने पर उसके पास से दो बैगों में रखा 15.654 किलोग्राम गांजा, एक पुराना रियलमी कंपनी का मोबाइल फोन तथा 500 रुपये नकद बरामद किए गए। आरोपी गांजा रखने एवं परिवहन करने संबंधी कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर

308 करोड़ की लागत से बन रहा केशकाल घाट बायपास, उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 5 जून को रुट का निरीक्षण कर कार्यों में तेजी लाने के लिए थे निर्देश

कोंडागांव /मूक पत्रिका। मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर दौरे के दौरान अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए थे। उन्होंने केशकाल बायपास के कार्यों में तेजी लाने को लेकर अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आज राष्ट्रीय राजमार्ग-30 रायपुर-जगदलपुर मार्ग पर बहुप्रतीक्षित केशकाल घाट फेरलेन बायपास रुट के निर्माण के लिए चयनित निर्माण



एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने अपने बस्तर प्रवास के दौरान 5 जून को विभागीय

अधिकारियों और निर्माण एजेंसी के साथ बायपास के दोनों छोरों का निरीक्षण कर इसके काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। उनके निरीक्षण के बाद विभाग ने आवश्यक कार्यावाहियां

तेजी से पूर्ण कर आज निर्माण एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिया है।

उप मुख्यमंत्री साव ने अधिकारियों और निर्माण एजेंसी से निर्माण सामग्री एवं निर्माण की पूर्ण गुणवत्ता सुनिश्चित करने हुए समर्थ-सीमा में काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बस्तर और छत्तीसगढ़ के लिए यह बायपास अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका तेजी से निर्माण कर आवाजाही शुरू करना सरकार की प्राथमिकता में है।

11.38 किमी का है बायपास, 2 वृहद और 2 मध्यम पुल भी बनेंगे- लोक निर्माण विभाग द्वारा 308 करोड़ रुपए की लागत से 11.38 किमी लंबे केशकाल घाट बायपास का निर्माण किया जा रहा है। इस बायपास में दो वृहद और दो मध्यम पुल भी बनाए जाएंगे।

28 जून से जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान, 96 हजार से अधिक बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई ने की अभिभावकों से अपील – प्रत्येक बच्चे को अवश्य पिलाएं पोलियो की दो बूंद

बेमेतरा/मूक पत्रिका

जिले में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का आयोजन 28 जून 2026 से किया जाएगा। यह तीन दिवसीय अभियान कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाई के निदेशन तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेखर के मार्गदर्शन में संचालित होगा। अभियान के माध्यम से जिले के शून्य से 5 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाकर उन्हें पोलियो जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अमृत लाल रोहलेखर ने बताया कि जिले में कुल 96,085 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के प्रथम दिवस 28 जून 2026 (रविवार) को जिलेभर में स्थापित पोलियो बूथों पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं दूसरे एवं तीसरे दिवस 29 एवं 30 जून 2026 को स्वास्थ्य



विभाग की टीमें घर-घर जाकर बूथों में छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगी। उन्होंने बताया कि विकासखण्डवार लक्ष्य के अनुसार बेमेतरा में 26,776, साजा में 22,074, नवागढ़ में 25,009 तथा बेरला में 22,230 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के दौरान पहुंचविहीन क्षेत्रों, ईट भट्टों, मेला-बाजारों, घुमंतू परिवारों तथा मलीन बस्तियों में विशेष मोबाइल टीमों के

माध्यम से बच्चों का चिन्हंकन कर उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, ताकि कोई भी बच्चा अभियान से वंचित न रहे। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. शरद कोहाड़े ने बताया कि अभियान की सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सेक्टर एवं मैदानी स्तर पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। अभियान के सफल संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग के साथ-साथ

लोधिया में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 18 लीटर महुआ शराब जब्त, आरोपी जेल भेजा गया..

सारगढ़-बिलाईगढ़/मूक पत्रिका

जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में बरमेकेला क्षेत्र के ग्राम लोधिया में आबकारी विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए अवैध महुआ शराब जब्त की है। कार्रवाई के दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार जिला आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में 11 जून को आबकारी विभाग की टीम ग्राम लोधिया पहुंची। मुखबिर से सूचना मिली थी कि गांव में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब का



भंडारण कर बिज्री की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने संबंधित स्थान पर पहुंचकर तलाशी ली। तलाशी के दौरान एक प्लास्टिक बोरी में रखी पॉलीथिन से 10 लीटर महुआ शराब और 40 पाउच में भरी 8 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। इस तरह कुल 18 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त की गई। अधिकारियों ने मौके पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए शराब को सीलबंद कर जब्त कर लिया। मामले में ग्राम लोधिया निवासी सुरेश सारथी (36 वर्ष) के खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2)

एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर सिंह राठिया, उपनिरीक्षक लोकनाथ साहू, मोहनलाल चौहान, रंजना टांडे, मुकुंद राम और डेलनारायण की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध शराब के निर्माण और बिज्री के खिलफ आगे भी लगातार कार्रवाई जारी रहेगी।

भीषण गर्मी में आग से बचाव को लेकर प्रशासन की अपील

अग्नि सुरक्षा के प्रति सतर्क रहें, छोटी सावधानी से टल सकती है बड़ी दुर्घटना

बेमेतरा/मूक पत्रिका

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन महानिदेशालय अग्निशमन सेवा, नई दिल्ली तथा मुख्यालय नगर सेना, रायपुर द्वारा ग्रीष्म ऋतु के दौरान जनजन की घटनाओं की रोकथाम एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि सुरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील है कि वे इन सुरक्षा उपायों का पालन कर स्वयं, अपने परिवार तथा संपत्ति को सुरक्षित रखें। बिजली एवं एलपीजी उपयोग में बरते विशेष सावधानी-गर्मी के मौसम में एयर कंडीशनर, कूलर, रेफ्रिजरेटर

एवं अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग बढ़ जाने से विद्युत भार अधिक हो जाता है, जिससे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि घर की विद्युत वायरिंग एवं उपकरणों का समय-समय पर निरीक्षण कराएं तथा केवल आईएसआई मानक वाले उपकरणों का ही उपयोग करें। उपकरणों का अनावश्यक एवं लगातार उपयोग न करें तथा उपयोग के बाद उन्हें बंद रखना सुनिश्चित करें। एलपीजी सिलेंडर को सदैव सीधी स्थिति में रखें और समय-समय पर साबुन के घोल से गैस रिसाव की जांच करें। खुले लौ वाले स्रोत जैसे दीपक, मोमबत्ती एवं अगरबत्ती को बिजली के सॉकेट तथा ज्वलनशील वस्तुओं से दूर रखें। आग से बचाव के लिए अपनाएं सुरक्षा उपाय, इन गलतियों से बचें- प्रशासन ने नागरिकों को सलाह दी है कि घरों एवं भवनों की बालकनी, गलियारे और सीढ़ियों को अनावश्यक सामान से मुक्त रखें ताकि आपातकालीन स्थिति में

रायगढ़/मूक पत्रिका

रायगढ़ में कानून-व्यवस्था इन दिनों काफी चुस्त और दुरुस्त है। एसएसपी शशि मोहन सिंह की 'कथनी और करनी' में कोई अंतर नहीं है, यह बात जगजाहिर है और अपराधियों में इसका खौफ भी है। लेकिन जरायम की दीवारें इतनी पुरानी और गहरी हैं कि कहीं न कहीं कोई सुराग रह ही जाता है। इसी सुराग से अब रायगढ़ में होटल और लॉज बिजनेस की आड़ में 'सेक्स सुविधा केंद्र' का एक सुरक्षित धंधा पनप चुका है। सब जानते हुए भी लोग खामोश थे, लेकिन आज जब वार्ड पार्श्व समेत आधा दर्जन से ज्यादा मोहल्लेवासियों ने रायगढ़ एसपी कार्यालय पहुंचकर कोतारा रोड स्थित 'व्हाइट रोज होटल' की गुंडागर्दी और

देह व्यापार के खिलाफ शिकायत दीज पहेली बार इस पूरे 'सेफर्सिड्केट' पर खुलकर पब्लिक का गुस्सा फूटा दिख रहा है!

स्टेशन के 500 मीटर में बिछा है मकड़ जाल, 5 सालों में 5 गुना बढ़ा धंधा-रायगढ़ में ऐसे कई होटल और लॉज हैं, जहां 'कपल्स' के नाम पर घंटे के हिसाब से 'सेक्स सुविधा' के लिए रूम किराए पर दिए जाते हैं। खासकर रेलवे स्टेशन के 500 मीटर के रेडियस में ऐसे लॉज कुकुरमुते की तरह फैल गए हैं। इनकी सभी से 'सेटिंग' इतनी तगड़ी होती है कि पिछले 5 सालों में इनका यह 'रंगीन कारोबार' 5 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। मुनाफ इतना है कि कई होटलों ने तो शहर में अपनी दो-तीन ब्रांच तक खोल ली हैं। बिना 'आधार कार्ड' के एंट्री? बस 1000 रुपये एक्स्ट्रा दीजिए! इन होटलों का अपना एक



अलग कानून चलता है। अगर आपके पास आधार कार्ड या कोई वैध आईडी नहीं है, तो भी कोई बात नहीं! बस 500 से 1000 रुपए अतिरिक्त (एक्स्ट्रा) दीजिए और बिना किसी रजिस्टर एंट्री के कमरा आपका। इन अय्याशी के अड्डों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि इनके बाहर आपकी हमेशा भारी मात्रा में दोपहिया वाहन (बाइक्स) खड़े मिल जाएंगे। मोहल्ले वाले अपने बच्चों पर पड़ रहे गलत असर को देखते हैं, सब समझते हैं,

होटल में नाबालिग लड़कियों और युवतियों को बुलाकर अनैतिक कृत्य कराया जाता है। होटल प्रबंधन की दबंगई इस कदर है कि जब इस गंदे खेल का विरोध बगल में रहने वाले पड़ोसी अरुण अग्रवाल ने 9 जून की रात करीब 12 बजे किया, तो होटल संचालक सूरज सिंह और उसके गुग्गों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अरुण अग्रवाल का सिर फेंक दिया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक, सिटी कोतवाली पुलिस की सुस्ती के कारण होटल संचालक के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह सर्रेआम कहता है:- 'मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने सबको खरीद लिया है।' फइनल ओपिनियन-फिनाल्ले यह पहेली बार है जब रायगढ़ की जनता ने ऐसे मामलों पर खुलकर शिकायत की है। इन होटलों और लॉज में जो

'खेल' चलता है, उसकी भनक स्थानीय पुलिस को न हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है! लेकिन आज तक इन पर इक्का-दुक्का कार्रवाई भी नहीं देखी गई, जिसके चलते लोगों का सिस्टम से भरोसा ही उड गया था और ऐसे सेक्स सुविधा केंद्र वाले लोगों के हौसले बुलंद! वरना कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं सबको खरीद लिया है.. ऐसे डायलॉग इतने कॉम्प्लेंट से नहीं बोलते।मामला सिर्फ 'व्हाइट रोज' होटल का नहीं है। वार्ड पार्श्व और जनता की इस लिखित शिकायत के बाद हो सकता है कि बाकी अय्याशी के अड्डे भी कुछ दिन के लिए 'अलर्ट' हो जाएं, लेकिन पुलिस की पैनी निगरानी से कोई बच नहीं सकता। जिस तरह बाकी बड़े और जटिल मामलों में रायगढ़ एसपी शशि मोहन सिंह ने त्वरित कार्रवाई कर मिसाल पेश की है।

सपा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्यों को दिया जा रहा है अंजाम

रायगढ़/मूक पत्रिका

सर्व नई समाज रायगढ़ अध्यक्ष तारा श्रीवास व रायगढ़ ब्यूटी एसोसिएशन की अध्यक्ष मंजुला त्रिपाठी की अगुवाई में दोनों ही संगठित टीम ने आज पुलिस अधीक्षक रायगढ़ के कार्यालय पहुंच कर एस एस पी शशि मोहन सिंह की कुशल कार्यशैली के लिए उन्हें बधाई दी व साथ ही ज्ञापन के माध्यम से अपनी कारोबारी पीड़ा व्यक्त करते हुवे बताया कि उनके रोजगार पर इन दिनों भारी संकट आ रही है जहां लोग यूपी झारखंड से लोगों को कारीगरी के नाम पर लाकर बसा रहे व आने वाले समय मे बांलादेशी घुसपैठ भी होने की आशंका भी उन्होंने जताई है इस पर सभी सेलून स्या संचालको और स्टायक की आई डी की जांच करने की बात उन्होंने ने ज्ञापन के माध्यम से की है । साथ ही उन्होंने अवगत कराया कि कि सपा सेंटर की आड़ मे अनैतिक कार्यों को भी अंजाम दिया जा रहा है जिससे कि उनका कारोबार बदनाम हो रहा है ऐसे स्या सेंटर बंद करवाने की मांग की है



साथ ही यूनिसेक्स सलूनो को बंद करवाने की मांग भी करते हुवे रात्रि 10 बजे सभी सेलून पार्लर सख्ती के साथ बंद करवाने व 10 बजे के पश्चात खुले सेलून पार्लरों के संचालकों पर कठोर कार्यवाही की मांग पुलिस अधीक्षक के समक्ष रखी ।

क्या कहते हैं तारा श्रीवास-हमें बड़ा अचरज होता है कि आज के महंगाई के इस परिवेश में जहाँ हमारे जाती भाई परिवार पोषण खर्च वहन के पश्चात पांच से दस हजार का किराया चुकता करने में असमर्थ हो रहे वहाँ बाहरी लोग तीस से चालीस हजार का किराया भाड़ा एकदम आराम से देते है ये जांच का विषय है ? सभी सेलून पार्लर स्या सेंटर के संचालक अपने दिमाग मे ये बात भली भाँति बैठ ले अब दुकाने रात्रि 10 बजे के बाद नही खुलेगी और ससाह में एक दिन मंगलवार को वर्करो को छुट्टी के साथ अपनी अपनी

दुकानों को बंद रखना होगा सम्झई चल रही है के किस्से कहानियां आप लोगों की नही सुनी जाएंगी ।

क्या कहती है मंजुला त्रिपाठी- सभी महिला ब्यूटी पार्लरों को रात्रि 9 बजे पश्चात बंद करने का सहयोग करना होगा साथ ही गैर रजिस्टर्ड बैनर के तले निजी जगहों पर सेमिनार के आड में हो रहे अकैध उगाही अनावश्यक पुरुष स्त्री के जमावड़े को बंद करे अन्यथा इसकी लिखित शिकायत की जाएगी । यूनिसेक्स सेलून पार्लरों और स्या सेंटर को बंद करवाने की मांग हमने की है अगर समय रहते इन सब चीजों पर अंकुश नही लगेगा तो हम उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाऐगे ।

इनकी राई उपस्थिति-तारा श्रीवास, मंजुला त्रिपाठी, अमित,उषेंद्र, संतोष श्रीवास, बंटी , खगेश, राजू ,लाला, महेश, रामनाथ, सुनील, नंदू, लगन, विजय,भोजराम, सुनील,सन्तोष, बबलू, ज्योति, प्रियंका, रोहिणी, बबिता,रंजन, सुमित्रा, ममता, शीतल।

केआईटी को कुर्क करने का आदेश, एक करोड़ वसूलकर कर्मचारियों को देंगे वेतन, लेबर कोर्ट का आदेश, प्रशासन ने केआईटी परिसर में खोले पांच संस्थान

एकमात्र सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज को बचाने के बजाय खत्म करने का प्रयास



वाला है। कैसे एक अच्छे-खासे शिक्षण संस्थान को बर्बाद किया जाता है, उसका सबसे सटीक उदाहरण केआईटी है। जिन प्राचार्यों के हाथ में केआईटी की कमान रही, उन्होंने इसका अवैध दोहन किया। कॉलेज की बीओजी ने तकनीकी शिक्षा मंत्री पदेन अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी ने घपले को रोका नहीं। इसमें कोई एक सरकार दोषी नहीं बल्कि सबका साझा अपराध है। रायगढ़ जैसे औद्योगिक जिले में युवाओं के लिए एकमात्र अर्द्धशासकीय इंजीनियरिंग

कॉलेज था, जिसको सरकार चलाती थी। चार साल से स्टाफ को वेतन नहीं मिला है। 40 कर्मचारियों ने लेबर कोर्ट में मुकदमा किया था।

कोर्ट ने 21 अप्रैल 2026 को आदेश दिया है कि किरोड़ीमल इंस्टीट्यूट की संपत्ति को कुर्क किया जाए। कर्मचारियों ने करीब एक करोड़ रुपए क्लेमया वेतन मांग था। अस्तुतः ने कहा है कि जब तक यह रकम न मिल जाए, तब तक संपत्ति को कुर्क रखा जाए। अब इसमें आगे की कार्रवाई